

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 जनवरी, 1974 (प्रथम बैठक)

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विषय-सूची

सोमवार, 14 जनवरी, 1974

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 27
सचिव द्वारा घोषणा	(10) 29
कार्य मन्त्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन	(10) 29
सदन पटल पर रखे गए कागज-पत्र	(10) 30
वर्ष 1974-75 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10) 31

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 16 जनवरी, 1974 (प्रथम बैठक)

विधान सभा को बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,
विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की

Mr. Speaker : The Question Hour please.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Co-operative Consumer Stores

***549. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the
Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of Co-operative Consumers Stores
in the State; and

(b) whether they are running in profit or in loss ?

**Minister of State for Co-operation and Local
Government** (Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan) : (a) 72

(b)	Profit	Loss
-----	--------	------

20

29

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगे
कि पार्ट 'ए' में जो उन्होंने बताया है उसकी जिलावार पोजीशन
क्या है? सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) रू

इस बारे में अध्यक्ष महोदय जिलावार पोजीशन इस प्रकार है । अम्बाला में दो सैट्रल और आठ प्राइमरी स्टोर हैं । कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम वाइड अप कर रहे हैं । लेकिन जिला अम्बाला में कोई नहीं है । कुरुक्षेत्र में एक सैट्रल, दो प्राइमरी और एक सैट्रल जो है उसे बंद करने जा रहे हैं । करनाल में दो सैट्रल, 9 प्राइमरी और इन में से दो प्राइमरी बंद करने जा रहे हैं । जीद में सैट्रल कोई नहीं पांच प्राइमरी और इन में से चार बंद करने जा रहे हैं । हिसार में एक सैट्रल, सात प्राइमरी और इन में से प्राइमरी दो को बन्द करने जा रहे हैं । भिवानी में एक सैट्रल, सात प्राइमरी और इन प्राइमरी में से चार को बन्द कर रहे हैं । महेन्द्रगढ में सैट्रल कोई नहीं 6 प्राइमरी और इन 6 में से 5 को बन्द करने जा रहे हैं रोहतक में एक सैट्रल पांच प्राइमरी और इन पांच में से दो को बंद कर रहे हैं । सोनीपत में सैट्रल कोई नहीं पांच प्राइमरी और बंद कोई नहीं कर रहे हैं । गुड़गांव में एक सैट्रल 9 प्राइमरी और 9 में से पांच को बंद करने जा रहे हैं । श्री गिरीश चन्द्र जोशी रू क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि अम्बाला का सुप्र बाजार प्राफिट पर चल रहा है और जगाधरीका जो कंज्यूमर कुआप्रेटिव स्टोर है वह घाटे पर चल रहा है तो क्या जगाधरी के स्टोर को अम्बाला के सुप्र बाजार की ब्रान्च बनाने की स्कीम है ताकि उस का काम ठीक चल सके और लौस में न जाये ?

श्री बनारसी दास गुप्त : इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो बंद करने की बात कर रहे हैं तो क्या कहीं पर नये खोलने का भी विचार है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: जहां आवश्यकता होगी वहां जरूर खोलेंगे ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो सेंट्रल और प्राइमरी स्टोर बंद करने जा रहे हैं उनके बंद करने का क्या कारण है?

श्री बनारसी दास गुप्त : उनका काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है । कोशिश तो बड़ी की कि उनके काम को इम्पूव किया जाए लेकिन जब वह इम्पूव नहीं हो पाया तो बंद करने का निश्चय कर लिया है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हिसार का जो स्टोर रहा है वह मुनाफे पर चल रहा है या नुकसान पर और अगर वह नुकसान पर रहा है तो क्या उसे बंद करने का विचार रखते हैं?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : वह नुकसान पर चल रहा है हम उसको इम्पूव कर रहे हैं और उसे बंद करने का विचार नहीं है ।

श्री के ० एन ० गुलाटी : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि कंज्यूमर स्टोर्ज की कमेटियां जो 16/12/73 को खत्म हो चुकी है उनकी नामीनेशन और इलैक्शन कब होंगे?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमैटरी इससे अराइज नहीं होता है

|

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो नुकसान में रहे हैं इनके नुकसान में चलने का कारण क्या है?

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, इसके कई प्रकार के कारण हैं । वह जो स्कीम है यह चाइनीज एग्रेसन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर प्रारम्भ की थी । सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसकी इनक्वायरी करवाई है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन्कवारी करवाई है । कई जगह ऐसा है कि इन में ज्यादा चीजें वह बेची जाती हैं जे कटरोल्ड आइटम्ब हैं जैसे शूगर, मिट्टी का तेल है और कई प्रकार के ऐसे जइटम्ज हैं जिन पर मारजिन आफ प्राख्य कम है । कई स्टोर ऐसे हैं जिन में प्रबन्ध कुशल आदमियों के हाथ में नहीं है । कोशिश यह की जा रही है कि अच्छे लोगों को इन स्टोर्ज में लगाया जाये । तो इ स प्रकार के कई कारण हैं जिमकी वजह से बह घाटे में चल रहे हैं । कोशिश यह है कि या तो इन स्टोज को इमप्रूव किया जावे और या फिर इनको वाइडअप किया

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो उन्होंने 20 स्टोर बताये कि मुनाफे में चल रहे हैं और 29 घाटे में चल रहे हैं तो पिछले साल जो घाटे में रहे उनको कितना घाटा हुआ और जो मुनाफे में रहे उनको कितना मुनाफा हुआ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : स्पीकर साहब, जो प्राफिट पर चल रहे हैं उनके प्राफिट की पोजीशन इस प्रकार है :

List of the Co-operative Consumers Stores Running
in Profit as on 30-6-1973,

Name of Store	Amount of profit
Faridabad (Central)	Rs. 3,000/-
Northern Rly. (Primary)	
Employees Kalka	Rs. 1,176/-
H.M.T.Pinjore	Rs.24,031/-
Ambala Cantt.	Rs. 5,676/-
Ambala Cantt. Sethi	Rs. 2,418/-
Mullana	Rs. 310/-
Jagadhri Railway	
Employees.	
	Rs.7,790/-

	Naraingarh	Rs. 473/-
	Shishu	Rs. 45/-
	Nilokheri ITC Centre	Rs, 2,079/-
1,025/-	Nilokheri T.C. Centre	Rs.
	Sonepat	Rs. 4,076/-
	Ganaur B.S.T.	Rs, 5,117/-
	Ganaur Mahavir	Rs. 5/-
	Textile Indl.	
	Workers Faridabad	Rs. 26,148/-
	Hyderabad Asbestors	
1,871/-	Employees Faridabad.	Rs.
50,274/-	Manohar at Dadri	Rs.
792/-	Hissar Textile Mill	Rs.
	Hansi Haryana	Rs.12,723/-
746/-	Jind Northern Rly. Employees	Rs.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो मुनाफा हुआ है यह कितनी सेल के अगेन्सट हुआ है?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन इस सवाल से एराइज नहीं होता चौधरी राम साल वधवा रू क्या वजीर साहब बतायेंगे कि करनाल के कज्यूमर स्टोर में घाटा है आंर उसका कारण क्या है?

श्री गोवर्धन दास चौहान : करनाल के स्टोर को 1,60,000 का घाटा है ।

चौधरी हरि सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे फि यह जो 72 स्टोर्ज हैं इन में से देहात में कितने थैं और शहरों में फितने हैं और अमर देहात में नहीं है तो क्या खोलने का विचार रखते हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ता : दिहात में जहां आवश्यकता होगी वहां खोलने पर विचार कर लेंगे ।

चौधरी धजा राम : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इन 72 स्टोर्ज के अन्दर कुल इनवैस्टमेंट कितनी है और वकिंग कैपीटल कितनी है?

श्री अप्यक्ष : यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नहीं है ।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे फि करनाल के स्टोर में जो 1,64,000 रुपये का घाटा है इसका कारण क्या है ?

श्री बनारसी दास गुप्ता : इसके कारण भी वही हैं जो मैंने पहले अभी-अभी बताये हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इन में कुल घाटा कितना है और इसे पूरा कैसे किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एराइज नहीं होता है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि तरावडी में जो मारकिटिंग एंड प्रासैसिंग सोसायटी है जिसके चौधरी शिव राम भी मैंबर हैं उस में जो गबन हुआ है उसकी क्या पोजीशन है?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एराइज नहीं होता है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हिसार के कंज्यूमर स्टोर मे चीनी के मामले में काफी गड़बड़ हुई है क्या कोई इस किस्म की शिकायत सरकार के पास आई है और अगर आई है तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एराइज नहीं होता है ।

Emporia Established

***569. Chaudhri Phool Singh Kataria :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total number of emporia established in the State as on 31st December, 1973 ; and

(b) the number and names of emporia running in profit and in loss, separately ?

Industries Minister (Shri Harpal Singh) :

(a) Six, including three Mini Emporia.

(b) Information cannot be supplied at this stage as the accounting year of the Haryana State Small Industries & Export Corporation which runs these Emporia closes on 30th June, 1974.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या यह एम्पोरियम्ज अगले साल कहीं और भी खोलने की योजना है?

श्री हरपाल सिंह : अभी तो कोई योजना नहीं है ।

चौधरी हरि सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इन एम्पोरिया में कौन कौन सी चीजें बेची जाती हैं और वइ कहां-कहां से आती हैं ।

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, वह जो एम्पोरिया बनाये गये थे इनके बनाने का मेन इडिया यह था कि हमारी स्टेट में जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज ह वे जो चीजें बनाता हैं उनको मारकिटिंग मिले बाहर एक्सपोर्ट के लिये भी और दूसरी स्टेट्स में बेचने के लिये भी, और आज हरियाणा में जितने यूनिट्सु हैं हैं डी-काफ्टस के, हैंड लूम के और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के, उन में जो माल तैयार होता है वह इन एम्पोरिया में डिसपले होता है और उसे बे सेल भी करते हैं। इससे मैनुफेक्चरज को हैल्प मिलती है क्योंकि ये उनका माल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। यह इम्पोरिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि हरियाणा का एम्पोरियम जो कैनाट प्लेस दिल्ली में है. उसकी सेल की क्या पोजीशन है दूसरी स्टेटों के मुकाबले में?

श्री हरपाल सिंह : दूसरी स्टेटों की इन्फर्मेशन देने के लिए तो सैप्रेट नोटिस चाहिए लेकिन जहां तक कैनाट प्लेस के एम्पोरियम को सेल का ताल्लुक है, उसमें बहुत अच्छी सेस है।

श्री अमर सिंह : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि सवाल के पार्ट (ए) के जवाब में बताया कि 6 एम्पोरिया हैं। क्या वे बतायेंगे कि वे कहा-कहां हैं और इनकी रोजाना सेल कितनी है? श्री हरपाल सिंह रु तीन एम्पोरिया बड़े हैं ओर तीन छोटे हैं।

जो बड़े हैं वे एक चण्डीगढ़, एक अम्बाला और एक नई-दिल्ली में है । छोटे एक पिंजौर, एक उचाना और एक सुलतानपुर में है ।

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि दिल्ली में जो इम्पोरिया चल रहा है उगमें सालाना क्या नफा रहा और क्या घाटा रहा?

Mr. Speaker : it is a separate question and not a supplementary.

Employment in Public Sector

***589. Shri Behari Lal Balmiki :** Will the Minister for Development be pleased to state-

(a) the steps taken by the Government to generate employment in the public sector;

(b) the total number of persons who got employment in public sector during the period from 1st May, 1968 to 31st December, 1973 ; and

(c) the steps taken further to provide jobs to the unemployed in the State ?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) :

(a) The following steps in general have been taken ;—

(i) The development programmes in the State have been intensified resulting in substantial employment opportunities particularly for the educated unemployed ;

(ii) The likely expenditure for the Fourth Plan would be Rs. 342 crores against an outlay of Rs. 225 crores.

The specific steps taken in this behalf are ;—

- (i) Special Employment Programme ;
- (ii) Half-A-Million Jobs Programme ;
- (iii) Crash Scheme for Rural Employment ; and
- (iv) Special Employment Programme for Educated Unemployed.

(b) According to Employment Market Information, employment in the public sector has increased from 137601 at the end of June, 1968 to 203078 at the end of June, 1973 providing additional employment to 65477 persons.

(c) Emphasis has been given in the Fifth Plan to labour intensive programme, where feasible, to provide more employment opportunities. The special employment schemes mentioned under item 'A' above are likely to continue during the Fifth Plan as well.

Pass Books to the Land owners

***604. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

- (a) whether the Pass Books have been supplied to the Land owners in the State ;
- (b) if so, the total number of Pass Books supplied to the landowners so far ;

(c) the total number of Pass Books yet to be supplied to the landowners in the State ; and

(d) the time by which the Pass Books as referred to in Part (c) above are likely to be supplied to the land owners ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) ;

(a) Yes.

(b) 6,31,514.

(c) 8,53,571.

(d) By the end of the year 1974.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने फरमाया कि 8,53,571 पास-बुक्स इशु करना बाकी रहती हैं । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इतनी जिले का क्या कारण है? क्या गवर्नमेंट डिले का कारण है या पटवारी?

Pandit Chiranji Lal Sharma : The pass-books are under preparation. There was some slackness for sometime. When I took over charge a decision was taken that Pass-books must be distributed as early as possible and instructions were issued accordingly and I hope, we will be able to distribute the remaining pass-books by the end of this year.

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या इस किस्म की कोई स्कीम है कि पास-बुक में जमींदार की जमीन की वैल्यूएशन भी लिखी जाएगी ? अगर जमीन की

वैल्यूएशन लिखी जाए तो ठीक रहेगी, क्योंकि किसान को कर्ज लेते वक्त सैप्रेट वैल्यूएशन लेनी पड़ता है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : The pass-books have already been , printed.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किसानों को पास बुक सप्लाई करने से कितना लाभ हुआ है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : It is just to facilitate the zamindars or the land-owners to know their position where they stand. Whenever any transactions take place, entries to that effect are made in the passbooks and they have not to go to the Patwari time and again.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि 8, 53,571 पास-बुकें सप्लाई करनी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक टोटल कितनी दे चुके । और जो बाकी रह गई हैं उन को कब तक इशू करने का इरादा है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : The reply is positively clear. In reply to part (b), I have stated that 6,31,514 pass-books have been distributed.

चौधरी दल सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया है कि 6,31,514 पास बुक्स तकसीम हो चुकी हैं । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इनकी डिस्ट्रिक्ट-वाइज तादाद कितनी है?

Pandit Chiranji Lal Sharma ; The district-wise information is as under :-

Hissar	1,66,291
Bhiwani	61,400
Rohtak	25,259
Sonepat	23,518
Gurgaon	48,304
Karnal	33,150
Kurukshetra	47,641
Ambala	1,09,779
Sind	61,203
Mohindergarh	54,961

Government Payment and Receipts

***733. Shri K. N. Gulati :** Will the Minister for Finance be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start the work of Government payments and receipts in the Treasury, NIT. Faridabad ; and

(b) if so, when it is likely to be finalized ?

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mittal) :

(a) No.

(b) Question does not arise.

Municipal Dispensaries

***679. Chaudhri Mehar Chand :** Will the Minister for Industries be pleased to state :

(a) the total number of Municipal Dispensaries in the State which have been provincialised during the period from 1st January, 1973 to date ; and

(b) the number of such Municipal Dispensaries which are likely to be provincialised?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) वर्ष 1973 के दौरान किसी भी नगरपालिका को डिस्पेंसरी का प्रान्तीकरण नहीं किया गया । तथापि अम्बाला कन्टोनमेंट बोर्ड हस्पताल का, उसके साथ लगती हुई 3 डिस्पेंसरियों सहित 19-12-173 को प्रान्तीकरण किया गया ।

(बी) नगरपालिका डिस्पेंसरिं फरीदाबाद (ओल्ड) का अगले वित्तीय में प्रान्तीकरण करने का प्रस्ताव है यदि वित्तीय साधन उपलब्ध

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि अम्बाला की डिस्पेंसरियो को लिया है, वहां स्टाफ पूरा था या नहीं?

श्रीमती शारदा रानी : स्टाफ पूरा नहीं था इसीलिए तो ली हैं ।

Home for Aged and Infirms

***695. Chaudhri Surjit Singh Mann :** Will the Minister for Social, Welfare and Taxation be pleased to state :

(a) the total number of aged and infirm persons residing in the Home for Aged, Infirms, Rewari as on 31st March, 1973 and

(b) the details of the facilities which are being provided to them?

Social Welfare & Taxation Minister (Shri Syham Chand) :

(a) 40/-

(b) Free boarding, lodging and medical facilities are provided to the inmates.

Shri Shyam Chand : That is a separate question and I need a separate notice for it.

चौधरी सुरजीत सिंह मान : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इनको कितना देते हैं?

श्री श्याम चन्द : 52 रुपये 50 पैसे माहवार ।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन को किस रिकमैण्डेशन पर लिया जाता है?

श्री श्याम चन्द : कोई आदमी जिसकी उम्र 55 साल हो और कोई और जिसकी आयु 60 साल हो उसको एस ० डी० ओ ० और तहसीलदार को रिकमैण्डेशन पर लिया जाता है?

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय इस मंहगाई के जमाने में इनका स्टाइपेंड दोगुना करने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम चन्द : पहले 35 रुपये था और इस साल रद्द कर साढ़े 52 किया है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस वक्त राज्य जितने होम हैं और क्या आगे अधिक खोलने का बिचार है? वक्त एडमिट हुए है इसलिए और होम खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

चौधरी राम लाल बधबा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि पिछले साल 40 एडमिट होने के लिए कितनी दरखास्ते आई थी? क्या रिकमैण्डेशन वाले सब आदमी दाखिल लिए हैं?

श्री श्याम चन्द : जिन की रिकमैण्डेशन आई थी वे सब एडमिट हो चुके हैं ।

श्री हरि सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो आदमी दाखिल होते हैं उनकी देखरेख के लिए क्या स्टाफ होता है?

श्री श्याम चन्द : सारा स्टाफ होता है जो रिक्वायर्ड है

|

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जींद में भी इस किस्म का होम खोलने का विचार है?

श्री श्याम चन्द : यह सारे हरियाणा का है और इसकी कपैसिटी 100 की हं । अगर जींद डिस्ट्रिक्ट में कोई हो तो हभ एडमिट कर लेंगे ।

श्री के 0 एन 0 गुलाटी : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इनको पैन्शन भी दी जाती है?

Starred Question No. 701

As the hon'ble Member was not present in the House, this Question was not put,

Western Jamuna Canal Augmentation Project

***710. Shri Girish Chander Joshi :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state

(a) the total expenditure incurred by the Government on the Western Jamuna Canal Augmentation Project in the State; and

(b) the additional area which is likely to be irrigated by this Project ?

Minister of State for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) Rs. 1361.39 lakhs, upto November, 1973.

(b) 1,38,000 acres.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि औगमेंटेशन कैनल बनने के बाद ट्यूबवैल्ज का पानी नीचे चला गया है, कम हो गया है या खारा हो गया है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : हमें कोई शिकायत नहीं आई और हमें यकीन है कि न पानी खारा होगा और न कम होगा ।

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस कैनल की कपैसिटी क्या है और इसके पानी को डिस्ट्रिक्स में किस तरह बांटेंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : यह सारा पानी वैस्टर्न जमुना कैनल में जाता है किसी पार्टिकुलर एरिये में नहीं जाता ।

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वाटर लोडिंग एरिये में जहां ट्यूबवैल्ज लगे हैं, उसमें कोई सुधार हुआ वे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : जी ही, खासी इम्प्रूवमेंट हुई है ।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, पानी नीचे हो जाने की कई शिकायतें आई हैं, क्या मन्त्री महोदय एक और सर्वे करवाने के इसिलिए तैयार हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

मुख्य मन्त्री (चौछरी बंसी लाल) : हकीकत यह है कि जहां से औगमेंटेशन कैनाल गुजरती है वह सारा इलाका वाटर लौग्ड था, बहुत बुरी हालत थी । अब इस कैनाल से कई हजार एकड़ जमीन काबलेकाश्त हो गई है ।

Upgradation of Schools

***550. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to up-grade the Primary Schools to Middle Schools and Middle Schools to High Schools in the State during the next financial year ; and

(b) if so, the district-wise names of such schools ?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मन्त्री (श्रीमति प्रसन्नो देवी)

:—

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चौधरी राम लाल बधबा : क्या मन्त्री महोदया बतायेगी कि अगले साल में अप-ग्रेड करने की कोई योजना है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : जी नहीं ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदया यह वताने की कृपा करेगी कि प्राईमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल अप-ग्रेड करवाने के लिए कितनी ऐप्लीकेशनज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग हैं?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब जब ये एक भी स्कूल अप-ग्रेड नहीं कर रहे हैं तो फिर ढिंढोरा किस बात का पीटते हैं..

..

Mr. Speaker : Order please. The reply has come. Not a supplementary question.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है?

मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल) : स्पीकर साहब, हकीकत यह है कि कोई डिसक्रिमिनेशन इनके साथ हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने इलाके में भी कोई स्कूल अप-ग्रेड नहीं कर रहे हैं ।

चौधरी राम लाल बधवा : क्या मंत्री महोदया बताएगी कि स्टूडेंट्स के लिहाज से जितने हाई स्कूल हैं वे कम नहीं ह?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : ऐसी कोई बात नहीं है ।

Haryana Land Ceiling Act, 1972

* **605. Chaudhri Dal Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether the Government has allotted any surplus land to the tenants or landless persons in the State out of the surplus area declared under the „Haryana Land Ceiling Act, 1972; and

(b) if so, the number of such tenants or landless persons together with their addresses and the area so allotted in Jind District ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Sir, before replying to this question, may I know whether the same question can be repeated in the same session ?

Mr. Speaker : The reply has come. It is the same reply which was given to previous question.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Still if you say, I will give the reply.

Mr. Speaker ; Part (b) of the question is about Jind District. But the reply is the same.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, the reply to this question is as under

(a) The Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972, came into force in the State of Haryana on the 22nd December, 1972. Under this Act, all those persons, who on 24.1.1971 held land in excess of the permissible limit, are required to submit the details of their land in the prescribed declaration form by 31.12.1973. In the case of the members of the Armed Forces, such declarations have to be filed by 27th August, 1974. It would be possible to allot surplus land to the tenants and landless persons only after such declarations have been received. So far, no land has been declared surplus or distributed under the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

(b) Nil.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब के मुताबिक सरप्लस जमीन डिक्लेयर करने की लास्ट डेट 31 दिसम्बर थी लेकिन बहुत से गांवों के अन्दर अनपढ़ लोग हैं, उनको इस बात का पता नहीं लगा ओर वे अपनी सरप्लस जमीन डिक्लेयर नहीं कर सके । तो क्या मिनिस्टर साहब, इस डेट को फरदर ऐक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं?

Pandit Chiranji Lal Sharma : No. The date was already extended by 43 days, otherwise declaration forms were to be filed by 28th of November.

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि भूमि जोत की लिमिट आपके डिपार्टमेंट ने कितनी असेस की है जो कि एक परिवार के लिए इको— नौमिकल रहे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : It is a legal question, Sir.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि इस वक्त तक कितने डैक्लेरेशन फार्म दाखिल हो चुके हैं?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Since 31st December was the last date, I could not collect this information. If the Hon. Member is particular, he should give notice and I will collect the information.

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग गलती की वजह से डैक्लेरेशन फार्म भर नहीं पाए उनके लिए डेट आगे बढ़ाने की कोई तजवीज है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : I have already replied.

X-Ray Plant in B.K. Hospital, Faridabad

***734. Shri K.N. Gulati :** Will the Minister for Industries be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that the X-Ray Plant in the B.K. Hospital, Faridabad, remained out of order from time to time ; and

(b) if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to keep the said X-Ray Plant in working order ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) : (ए) तथा (बी) बी. के. हस्पताल फरीदाबाद के दो एक्स-रे प्लॉट्स में एक मेन प्लान्ट अप्रैल, 1973 के आरम्भ से एक अगस्त, 1973 तक खराब रहा जोकि मुरम्मत और नये पुर्जे लगाने के बाद सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । दूसरा प्लान्ट पूरा समय सन्तोषजनक ढंग से कार्य करता रहा है ।

श्री के० एन० गुलाटी: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि पिछले दो तीन साल से इस ऐक्स-रे प्लांट की रिपेयर पर कितना पैसा खर्च किया गया है?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, यह एक ही बार खराब हुआ था और पैसा खर्च होने के बारे में क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं था इसलिए इस समय मैं बता नहीं सकती ।

श्रीमती लेखवती जैन : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि अम्बाला का ऐक्स-रे प्लांट कितने दिनों से खराब पड़ा है? स्पीकर, साहब इसी हाउस के एक आनरेबल मैम्बर राव अभय सिंह जी के हाथ में जब चोट लग गई तो उनको लेकर ऐक्स-रे करवाने के लिए मैं वहां पर गई लेकिन वहां पर बताया गया कि प्लांट खराब पड़ा है । इस वजह से उन्हें ऐक्स-रे करवाने के लिए चंडीगढ़ आना पड़ा ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

Shrimati Lekhwati Jain : I should get a reply

Mr. Speaker : Order please. The question is about Faridabad. How can she give a reply about Ambala ?

श्रीमती लेखवती जैन : स्पीकर साहब, कम से कम वे यह तो बता दे' कि वह कब तक ठीक हो जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : जनाब, अम्बाला का ऐक्स-रे प्लांट खराब है, यह मेरे नोटिस में नहीं था लॉकन अब हमने हिदायत करदी है कि जहां भी ऐक्स-रे प्लांट खराब हो जाता है वहा सी० एम ० ओ ० अपने लैवल पर तुरन्त ठीक करवाने की कार्यवाही कर ले ।

श्री के ० एन० गुलाटी : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि चूंकि यह प्लांट बार बार खराब हो जाता है इसलिए नया प्लांट खरीदने का इंतजाम किया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी: जनाब वहां दो प्लांटस है । यह जो प्लांट है यह सिर्फ एक ही बार खराब हुआ था, बार-बार खराब नहीं हुआ । यह बहुत पुराना प्लांट है औत्र युनिसिफ द्वारा हमको मुफ्त में दिया गया कप । जब यह बिल्कुल खराब हो जाएगा वर्किंग आर्डर में नहीं रहेगा, तो द्वारा खरीद लेगे ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि करनाल का ऐक्स-रे प्लांट भी खराब पड़ा हुआ है?

श्रीमती शारदा रानी : जी नहीं ।

श्रीमती लेखवती जैन : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहिबा ने पहले तो बताया कि नालेज में नहीं है लेकिन फिर कह दिया कि मैंने आर्डर कर दिया है कि जहां भी प्लांट खराब हो सी०एम ०ओ ० ठीक करवा ले । क्या वे अम्बाला के बारे में खास तौर पर बताएंगी कि उसे कब तक ठीक करवा दिया जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी: वह मैंने सभी के लिए बताया था ।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने अभी माना है कि जो ऐक्स-रे प्लांट फरीदाबाद के लिए लिया गया है वह खराब हो जाता है । क्या वे बताने की कृपा करेंगी कि जब ये खरीदे जाते हैं तब गारंटी नहीं ली जाती?

श्रीमती शारदा रानी: स्पीकर साहब, यह तो मुफ्त में आया हुआ है ।

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह) : स्पीकर साहब, प्लांट को लाईफ 10- 12 साल की होती है । कई प्लांटस पुराने हैं और उनका कोई न कोई पुर्जा खराब हो जाता है कम्पनी वाले कई दफा पुर्जे बाहर से मंगवाते हैं और बाहर से मंगवाने में कई दफा देर भी लग जाती है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदया फरमायेंगी कि जब तक बहन लेखवती जैन दुबारा वहां जाएंगी तब तक वह ऐक्स-रे प्लांट ठीक हो जाएगा? --(हंसी)--

श्रीमती लेखवती जैन : मुझे तो किसी न किसी के साथ जब भी ऐक्सीडेंट होता है रोज ही जाना पड़ता है । (विघ्न)

श्री अमर सिंह : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि फरीदाबाद का जो ऐक्स-रे प्लांट खराब हो गया था वह कब खरीदा था और कब खराब हुआ?

श्रीमती शारदा रानी : यह अब से 18 वर्ष पूर्व खरीदा गया था और यूनिसिफ से यह हरियाणा को मुक्त में मिला था । यह साईमन का है और वैस्ट जर्मनी का बना हुआ है और इस समय बहुत अच्छी हालत में काम कर रहा है ।

X-Ray Plants

***680. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Industries be pleased to state :-

(a) the district-wise total number of Hospitals where the X-Ray plants existed as on 1st May, 1968 together with the district-wise total number of Hospitals, where this facility has been provided during the period from 1st May, 1968 to 31st December 1973; and

(b) whether this facility is likely to be further provided in more Hospitals in the State during the next financial year, if so, the names of such Hospitals ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) वांछित सूचना हाउस के टेबल पर रखी जाती है (विवणी I-II)

(बी) नहीं ।

Statement—I

Names of Hospitals where X-Ray facilities existed
before 1,5.1968;

District Ambala

1. Civil Hospital, Ambala.
2. Civil Hospital, Naraingarh. District Karnal
3. Civil Hospital, Karnal.
4. Civil Hospital, Panipat.
5. Civil Hospital, Kaithal.

District Hissar

6. Civil Hospital, Hissar.
- 7: Civil Hospital, Fatehbad.

District Bhiwani

- 8: Civil Hospital, Bhiwani.
9. Civil Hospital, Dadri

District Rohtak

10. Civil Hospital, Rohtak.
11. Civil Hospital, Bahadurgarh.
12. Medical College Hospital, Rohtak.

District Gurgaon

13. Civil Hospital, Gurgaon.
14. B.K. Hospital, Faridabad.

District Mohindergarh

15. Civil Hospital, Narnaul. 16: Civil Hospital,
Rewari.

District Sonapat

17. Civil Hospital, Sonapat. District Kurukshetra.
18. Referral Hospital, Kurukshetra. District Jind.
19. Civil Hospital, Jind.
20. Civil Hospital, Narwana.
21. Civil Hospital, Safidon.

Statement—II

District-wise total No. of Hospitals where X-Ray facilities have been provided during the period from 1-5-1968 to 31-12-1973.

District Hissar

1. Civil Hospital, Hansi.

2. Civil Hospital, Adampur.
3. Civil Hospital, Mandi Dabwali.
4. Civil Hospital, Sirsa.
5. Civil Hospital, Tohana.
6. T.B. Hospital, Hissar.

District Rohtak.

7. Civil Hospital, Jhajjar.
8. C.R, Dass Mobile Hospital, Rohtak.

District Gurgaon.

9. Civil Hospital, Ferozpur Jhirka.
10. Civil Hospital, Nuh.
11. Civil Hospital, Palwal.

District Kurukshetra.

12. Civil Hospital, Shahbad.

District Ambala.

13. Civil Hospital, Ambala Cantt.
14. Civil Hospital, Kalka.
15. Civil Hospital, Jagadhri.
16. M.L. Civil Hospital, Yamunanagar.

District Mohindergarh.

17. Civil Hospital, Mohindergarh.

District Bhiwani.

18. Civil Hospital, Tosham.

19. Civil Hospital, Loharu.

District Sonapat.

20. Civil Hospital, Gohana.

चौधरी मेहर चन्द : क्या मंत्री महोदया से मैं यह पूछ सकता हूँ कि वे पार्ट (बी) का उत्तर 'न' में ही क्यों देती हैं, कभी तो रहा कर दिया करें? (हंसी)

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, इन्होंने पूछा या कि क्या 1974-75 में कहीं ऐक्स-रे प्लांट्स दे रहे हैं? इसके बारे में मैंने पहले भी कह दिया था कि नशे दे रहे हैं उसी प्रश्न को बार-बार पूछें तो जवाब तो इनको हर बार 'नहीं' में ही मिलेगा

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जो लोग अस्पताल में ऐक्स-रे करवाने जाते हैं, उनसे कुछ चार्जिज लिए जाते हैं या मुक्त ही किया ?

श्रीमती शारदा रानी : कुछ केसिज में मुफ्त किया जाता है लेकिन जो लोग वहाँ पर दाखिल नहीं होते हैं या बाहर से इलाज करवाने के लिए जाते हैं उनसे चार्जिज लिए जाते हैं ।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि अस्पताल में ऐक्स-रे प्लांट से जो ऐक्स-रे कराते हैं उनसे चार्जिज लेने के लिए इन्कम की कोई लिमिट रखी गई है?

श्रीमती शारदा रानी : जी हां ।

चौधरी शिव राम वर्मा : कक्या मत्री महोदया को मालूम है कि मैडिकल कालेज रोहतक के हस्पताल के डैन्टल विंग का ऐक्स-रे प्लांट कई दिनों से खराब पड़ा है क्या दे यह भी बताने की कृपा करेंगी कि वह कब तक ठीक हो जाएगा?

Mr. Speaker : Order please. This is not a supplementary question.

Facilities to Blinds

***696. Chaudhri Surjit Singh Mann;** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state :-

(a) the total number of blind persons who are getting education and vocational training in the Institution for Blinds located at Panipat and Sonapat as on 31st March, 1973 ;

(b) the details of the facilities which are being provided to them; and

(c) whether any arrangement have been made for providing jobs. to such persons after their getting training from there ?

Social Welfare & Taxation Minister (Shri Shyam

Chand) :

(a) (i) Govt. Institute for the Blind, Panipat.

(ii) Training Centre for the Adult Blind, Sonapat.

(b) Free boarding, lodging, medical, educational and training facilities are provided to the inmates in these Institutions.

(c) A Production Unit is being set up for providing gainful employment to the inmates after their training during the current financial year.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेगे कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको जाब प्रोवाइड हुई हुं?

10.00 बजे ।

Shri Shyam Chand : I need a separate notice for this.

श्री के ० एन ० गुलाटी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कोई ऐसी योजना है कि और बलाईड हाउसिज खोले जायें ताकि उनको उसी के काम पर लगाया जा सके?

श्री श्याम चन्द : बलाइन्ड हाउसिज खोलने की कोई योजना नहीं है । हां हाउसिज फार बलाइन्ड खोलने की योजना को कन्सिडर कर रहे हैं ।

श्री अमर सिंह क्या : मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो इस समय ट्रेनिंग दी जाती है वह कितने साल की है और कितने साल के बाद उनको जौब मिल जाता है?

श्री श्याम चन्द : तीन साल की ट्रेनिंग है ।
Employment depends upon the availability of posts and other factors.

चौधरी रामलाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे अगर किसी को काम सीखने के पश्चात जौब नहीं मिलता है तो क्या उनको कोई और काम देंगे जिससे उनको कोई इन्कम हो सके?

Shri Shyam Chand : There is a production centre, Sir, where these blinds are employed. We have also requested all these industries to provide employment to these blinds and other handicapped.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो पोलिटिकल तौर पर अन्धे हैं उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग स्कूल खोलने की योजना है? (हंसी)

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पानीपत और सोनीपत में जो बलाइन्ड इंस्टीट्यूशन हैं उनमें ऐसे कितने ट्रेन्ड परसन हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिली है?

Shri Shyam Chand ; At Panipat and Sonapat, we have provided training facilities. So, I don't have the information asked for with me. The Hon. Member may please give a separate notice for this.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जहां-जहां पर सैन्टर बोले गये हैं और उनमें जो सामान बनाते हैं, क्या उस सामान को खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने दफतरो में यह हिदायत कर रखी है कि नहीं से सारा सामान खरीदें जो वहां बनता है?

Shri Shyam Chand ; Yes, we have requested all the Departments.

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो अन्धे लोग वहां से काम सीख कर निकलते हैं, तो क्या सरकार की उनको कोई ग्रान्ट या लोन देने की प्रापोजल है जिससे वे अपना काम कर सकें?

Shri Shyam Chand ; Every grant and loan is given on merits.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने ऐसे ट्रेन्ड आदमी हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है?

Shri Shyam Chand : I need a separate notice for this.

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हरियाणा में पानीपत और सोनीपत में ही ये इन्स्टीटयुशन क्यों हैं? क्या पानीपत और सोनीपत में ज्यादा अन्धे हैं या दूसरी जगहों पर भी है?

Shri Shyam Chand : These two places are centrally located places and people from all the States come to these places.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार कितना रुपया सालाना खर्च कर रही है ?

Shri Shyam Chand : The entire expenditure is met by the State. As to the expenditure, it depends upon the strength of the inmates in these centres.

Starred Question No. 702

As the hon'ble Member was not present in the House, this question was not put .

Concessions to the Students belonging to Scheduled Castes

and Backward Classes

***706. Shri Jagjit Singh Tikka** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the details of concessions given to the

students belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in the state ;

(b) the maximum limit of income of the parents of the children to whom the concessions as referred to in part (a) above are given ; and

(c) whether the government intends to increase such limit keeping in view the rise in price ?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित छात्रों को निम्नलिखित शिक्षा सुविधाएं भिन्न-भिन्न योजना के अधीन प्रदान की जाती हैं—

- 1 छात्रवृत्तियां ।
2. ट्यूशन फीस तथा अन्य अनिवार्य शुल्क एवं निधि से छूट ।
- 3 परीक्षा प्रवेश शुल्क को प्रति पूर्ति ।
- 4 हरिजन छात्रों को नौवीं, दसवीं तथा ग्यारवीं कक्षाओं में उच्चतर दर से विशेष योग्यता छात्रवृत्तियां ।
- 5 छात्रावासी छात्रों को अतिरिक्त मुक्त छात्रवृत्तियां ।
- 6 प्राईमरी स्कूल के छात्रों को मुक्त पाठ्य-पुस्तकों तथा लेखन- सामग्री ।

(ख) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के माता-पिता की अधिकतम आय सीमा निम्न प्रकार है :

पूर्व मेट्रिक स्तर

मैट्रिक उपरान्त स्तर

(1) अनुसूचित जाति 1507 /- मासिक 500 /-

के छात्र

(2) पिछड़े वर्ग के छात्र 150 /- मासिक 150 /-

(ग) हां सरकार ने अभी-अत्री आय सीमा 150 रुपये मासिक से 350 रुपये मासिक करने का निर्णय ले लिया है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मवी महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि इस बढ़ती हुई प्राइसीज को देखते हुए क्या सरकार छात्रवृत्तियां बढ़ाने पर भी विचार कर रही है? दूसरा यह है कि जैसे कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसकी फीस लग जाती है तो क्या उसकी फीस एक साल के लिए और माफ करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : जहा तक छात्रवृत्तियां बढ़ाने का सवाल है वह तो हमने सन् 1970-71 में 12 लाख 47 हजार की दी हैं, 1971- 72 में 17 लाख 70 हजार की, 1972-73 में 22 लाख 10 हजार को और सन् 1973- 74 में 24 लाख 65 हजार रुपया दिया है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदया बतायेंगे कि यह जो राशि बढ़ती जा रही है यह स्टूडेंट को संख्या बढ़ने से बढ़ती जाती सैं या वजीफे की दर बढ़ायी जा रही है?

शिक्षा मंत्री (चौधरी माडु सिंह) : स्टूडेंट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है दूसरे हमने दर भी बढ़ायी है । छः रुपये से 8 रुपये कर दी है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सन् 1972- 73 में कुल कितने स्टूडेंट्स को लाभ हुआ?

श्रीमती प्रसनी देवी : 3678 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं और जो छात्र होस्टलों में रहते हैं उनको 15 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से अलग दिया है । इस तरह से 275 छात्रों को होस्टल में रहने वालों को दिया है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या इस दर को और बढ़ाने को सम्भावना है?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहिब अभी पिछले साल ही छः रुपये से 8 रुपये यह दर को है ।

चौधरी दल सिंह : जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि बैकवर्ड और शिडयुल्ड कास्ट के बच्चों को जो यह छात्रवृत्तियां दी वे । मैं यह जानना चाहता हू कि जो ऐसे तालबेलम हैं जिनकी अपनी जमीनें नहीं है, वे शिडयुल्ड कास्टस

या बैकवर्ड क्लास के नहीं हैं तो क्या उन स्टुडेंट्स को भी यह रियायतें देंगे?

श्री माडू सिंह मलिक : 1800 रुपये से कम सालाना आमदनी वाले सभी बच्चों को फीस से छूट दी जाती है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदय यह बताने को कृपा करेंगे कि जो राशि हरिजन बच्चों और दूसरे स्टुडेंट्स को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है क्या यह वजीफे वाली राशि उसमें शामिल है?

श्री माडू सिंह मलिक : उससे अलहदा है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह राशि सन् 1967- 68 में कितनी दी जाती थी?

श्री माडू सिंह मलिक : उसके लिए तो नोटिस चाहिए ।

Import of Raw Material

***711. Shri Girish Chander Joshi :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the number of Essentiality Certificates issued alongwith the value thereof for the import of raw material in the State during the period from 1st April, 1968 to 31st March, 1973, separately ;

. (b) the names of the main scarce raw materials for which the said certificates were issued during the period as

referred to in part (a) above; and

(c) whether there is still some scarcity of raw materials as referred to in part (b) above; if so, the steps taken by the Government to remove the scarcity ?

Industry Minister (Shri Harpal Singh)

(a), (b)&(c) A statement is laid on the table of House.

(a) The number of Essentiality Certificates issued alongwith their value from 1-4-68 to 31-3-73 years-wise is given below :—

	Year recommended	No. of Essentiality Certificates issued	Value
1.	1968-69	292	Rs. 45,97,469/-
2.	1969-70	664	Rs. 1,35,14,792/-
3.	1970-71	1149	Rs. 4,49,75,647/-
4.	1971-72	889	Rs. 4,92,97,251/-
5.	1972-73	922	Rs. 2,93,52,000/-

(b) The names of main imported scarce raw

materials are Copper, Zinc, Lead, Tin, Mercury, Stainless Steel Sheets and Strips, Die Steel, Alloy Steel, Wire rods, various types of Fine Chemicals, Organic Inorganic Chemicals like Titanium Dioxide, Lithophone, High/Low density Moulding powders etc.

(c) There is still scarcity of imported raw materials and Government of India have, therefore, allowed their continued import.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जो (सी) पार्ट के जवाब में बताया गया है कि असैसियेलिटी सर्टिफिकेट दिया है, क्या अब भी कच्चे माल की स्केयोरिटी है और अगर है तो किन चीजों की है

Shri Harpal Singh : Sir. I have already stated in answer to part (c) of the question that there is still scarcity of imported raw-materials and Government of India have, therefore, allowed their continued import.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कितने ई0 सी 0 रिकमैड किये जाते हैं उन सब को इम्पोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे पास फिगजं हैं, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूँ । 1968-67 में 292 को इम्पोर्ट

लाइसेंस मिला जो कि रिकमैड किये हुए थे, 1979- 70 में 664 को, 1970- 71 में 1149 को, 1971- 72 में 889 को और 1972- 73 में 922 को इम्पोर्ट लाइसेंस मिला ।

चौधरी राम लाल वधवा : दया मंत्री महोदय यह बताने को कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि हरियाणा से जितने ई ' सी ' रिकमैड किए जाते ह उतनों को इम्पोर्ट -लाइसेंस मिलता नहीं है? क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि फरीदाबाद में एक ऐसा सैल खोल दिया जाए जो इंडस्ट्री वालों को इ म्पोर्ट लाइसेंस दिलवाने में सहायता करे-?

श्री हरपाल सिंह : स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये जो असैशीयेलिटी सर्टिफिकेट होते हैं, वह हमारा डायरक्टर स्पॉन्सर करता है । लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए डायरे स्टर जनरल आफ टेक्निकल डिवैल्पमेंट जो देहली मे है, असैशीयेलिटी सर्टिफिकेट स्पॉन्सर करता है । सरकार का जो काम होता है वह सिर्फ स्पॉन्सर करने का होता हूँ । अगर किसी इडछियलिस्ट कोई डिफीकल्टी आये और वह हमारे नोटिस में लाये तो हम उसको बाकायदा परन्तु करते हैं । हमारे नोटिस में ऐसी कोई डिफींकल्टी नहीं आई है ।

श्री अमर सिंह : क्या मंजे महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रा- मैटीरियल इम्पोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट

असेंशियरीलटी सर्टिफिकेट रिकमंड करती है इसका काइटेरिया क्या है यानी किस आधार पर रिकमैडेशन की जाती है?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में पोजीशन यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हर साल फर्स्ट अप्रैल को अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पालिसी अनाउन्स करती है, उसकी एक रैंड बुक बन जाती है । उसमें यह सब कुछ दिया होता है कि अगले साल के लिए यह-यह पैटर्न होगा-इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए और क्या-क्या आईटम्ज होंगी, कौन सी इंडस्ट्री को प्रायरिटी पर कन्सीडर किया जाएगा और कौन-कौन सी आईटम्ज इम्पोर्ट हो सकेंगी । ये सारी डिटेल्ड उस किताब में प्रिन्ट कर दी जाती हैं और उसमें जो पालिसी दी होती है उसके मुताबिक ही डायरेक्टर यह देखकर कि कितनी मशीनरी की वैल्यू है, कितनी उसकी कैपेसिटी है और क्या वह इंडस्ट्री प्रायरिटी में आती है, अपनी रिकमैडेशन करता है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए सब से ज्यादा हमें आयरन और स्टील की जरूरत रहती है, सरकार इस कमी को दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर में कोई कारखाना हरियाणा में खोलने पर विचार करेगी?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, अभी हम एक स्टील बिलेट्स का कारखाना हिसार में शुरू कर रहे हैं और इसी तरह

से एक और कारखाना स्पंज आयरन का खोलने के बारे में दम ऐगजामिन कर रहे हैं । टैक्नीकल नो-हाऊ ऐक्सपर्ट्क्ष से इस बारे में अशोरेन्य भिलने पर हम स्पंज आयरन का एक प्रोजैक्ट हरियाणा में चालू करने जा रहे है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मंजई महोदम यह वताने की रुपा करेंगे कि यह सच है कि 1972-73 और 1973-74 के अन्दर यहां से चमड़ा बाहर के देशों को बहुत गया है जिसकी वजह से मजदूर लोग काफी बेरोजगार हो गए है? मेरे ख्याल में इसको और इम्पोर्ट न करें तो अच्छा है ।

गृह मन्त्री (थी के 0 एल 0 पोसवाल) : यह तो ऐक्सपोर्ट का मामला. हे?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी पीर चन्द जी को तो चमड़े का ही ख्याल लगा रहता है । यह तो आयरन और स्टील से सम्बन्धित सवाल है ।

Mr. Speaker : The Question hour is over.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 274

विषय—अतारांकित प्रश्न नं 0 274—चौधरी राम लाल,
एम 0 एल0 ए 0

अतारांकित प्रश्नों की 16- 1- 1974 की सूची में चौधरी राम लाल, एम 0 एल 0 ए0 के नाम दर्ज विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 274 का उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ । ज्यों ही सम्बंधित सूचना इकट्ठी हो जाएगी, अपेक्षित उत्तर भेज दिया जाएगा ।

ह/0 महा सिंह

कार्यकारी मन्त्री ।

सेवा में

अध्यक्ष

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़ ।

अशा: क्रमांक डी० पी० जी०-4-74/2227
चण्डीगढ़, दिनांक 15 जनवरी, 1974''

Haryana Bhawan

275. Chaudhri Dal Singh : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the number of officers of Haryana Government stayed at Haryana Bhawan, Delhi, since its completion to date year-wise i.e. on official duty and on private work;

(b) the amount of rent recovered from the officers who stayed at Haryana Bhawan, Delhi, as referred to in part (a) above;

(c) the total expenditure incurred by the Government on the maintenance of the said Bhawan and on the Government employees working in Haryana Bhawan, Delhi, during the year 1971-72 and 1972-73, separately; and

(d) the number of M.L.As. and private persons who stayed at Haryana Bhawan, Delhi, alongwith their addresses in official or private capacity during the years 1971-72 and 1972-73, separately, and the amount of rent charged from each of them for that period ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी साल) :

(ए) वर्ष	अधिकारियों की सरकारी		
गैर-सरकारी	संख्या		
1970-71	1018	921	97
1971-72	2366	2231	135
1972-73	2931	2811	
129			
1973-74	1969	1879	

(1-4-73 से

31-12-73 तक)

(वी) वसूल किया गया किराया

वर्ष	सरकारी यात्रा पर	गैर-सरकारी
यात्रा पर	रुपये	पैसे
1970-71	7964-67	528-00
1971-72	1957-00	2058-00
1972-73	21700-00	2731-00
1973-74	23056-500	1642-00

(1 -4-73 से

31 - 12- 73 तक)

(सी) मेंटीनैस पर आया खर्च

वर्ष	रुपये	पैसे
1971-72	3,17,725-	00
1972-73	3,97,220-	00

अस्टैबलिशमेंट पर आया खर्च

वर्ष	रुपये	पैसे
1971-72	1,10,554	00
1972-73	1,06,301	00

(डी) सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ न होगा ।

Mr. Speaker : Secretary will now make an announcement.

सचिव द्वारा घोषणा

Secretary : Sir, I have to inform the House that the Haryana Minerals (Vesting of Rights) Bill, 1973, which was passed by the Haryana Legislative Assembly in its last session on the 14th November, 1973, has been assented to by the President.

कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन

Mr. Speaker : I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in their Fourth Report in regard to various business as under :

The Committee met in the Chamber of the Speaker on Tuesday, the 15th January, 1974, at 4.00 P.M.

"The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 16th, 17th and 18th

January, 1974, be transacted as follows:—

16th January, 1974

1st Sitting at 9.30 A.M.

1. Questions Hour.
2. Fourth Report of the Business Advisory Committee.
3. Laying of the Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1973, on the table of the House.
4. Resumption of General Discussion on Budget.

2nd Sitting at 2-00 P.M.

1. No. Questions Hour.
2. Discussion and voting on Demands for Grants on Budget.

17th January, 1974

1st Sitting at 9.30 A.M.

1. Questions Hour.
2. Nonofficial Business.

2nd Sitting at 2 P.M.

1. No Question Hour.
2. The Haryana Appropriation Bill on Budget.

(One Hour only)

3. Other Legislative Business.

18th January 1974, (9-30 A .M.)

1. Questions Hour.
2. Motion under rule 16 regarding adjournment of the Assembly sine-die.
3. Presentation of Preliminary Report of the Committee of Privileges.
4. Papers/Reports, if any, to be laid on the Table of the House.
5. Motion regarding the extension of the term of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Legislative Business."

Home Minister (Sh. K.L. Poswal) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee,

The motion was carried

सदन के पटल दर रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now a Minister will lay on the Table a copy of the notification.

Home Minister (Sh. K. L. Poswal) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the notification No. G.S.R. 3/H.A. 35/73/S. 25/74, dated the 4th January, 1974, regarding the Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1973, as required under section 25(3) of the Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1973.

वर्ष 1 974-75 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Budget. Shri Girish Chander Joshi may please resume his speech.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि सरकार ने और वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट अनुमान हमारे सामने रखे हैं, उसके पीछे एक मैंसे बड़ी (अच्छी) भूमिका यह है कि हम बचत करें । हम जानते हैं कि फिजूलखर्ची को दूर करके बचत की जा सकती है । वेस्टफुल

ऐक्सपैडीचर जो है, वह तो नहीं होना चाहिये लेकिन गेनफूल ऐक्सपैडीचर जरूर होना चाहिये क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते । गेनफूल ऐक्सपैडीचर उन्ही मदों पर होगा जो प्रोडक्टिव हैं, ऐम्पलायमेंट ओरियेन्टड हैं, जिनसे हमारे प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और जिनसे हमारी प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी । हमारी यह कोशिश हो कि हम गेनफूल ऐक्सपैडीचर की बुनियाद पर अपने देश में जराये पैदा करे,अपने देश में ऐसे साधन पैदा करें ताकि हम इकोनोमी को री-ओरीएन्ट करें और री-जमरेट करें । कोशिश सिर्फ सरकार से ही नहीं, जनता की तरफ से भी होनी चाहिये । सरकार ने तो अपनी देश से इस ओर इशारा किया है और इसके साथ ही साथ जनता की तरफ भी इशारा किया है यह वे भी अपने खर्च में बचत करें । खर्च में बचत करने से खुद जनता को फायदा होगा । बचत तरफ जनता सरकार को भी फायदा कर सकती हूं । यदि जनता अपने खर्च में बचत करेगी तो सरकार उस पैसे को बिजली की तरफ या दूसरे भलाई के कामों में लगा सकेगी जिनकी तरफ जनता खर्च करना चाहती है या उसकी खर्च करवाने की ख्वाहिश है । बचत करने के लिये हमें आस्टैरिटी रखनी पड़ेगी । हमें अपनी जरूरत की चीजों के अलावा ऐसी चीजों को नहीं लाना होगा जो इस वक्त हमें दरकार नहीं हैं या जिनसे इस वक्त काम चल सकता है । हमें हर तरीके से बचत करनी पड़ेगी और इस बचत की बुनियाद पर जो सेविंग हम करेंगे, अगर हम वह सेविंग सरकार को दें तो सरकार के पास इन्वैस्टमेंट करने का एक साधन पैदा होगा और उसकी सहायता में

सरकार जनता को वह चीजे उपलब्ध करायेगी जो जनता के फायदा के लिये हो । यह एक बुनियादी असूल वित्त मंत्री जी ने अपने बजट अनुमानों में हमारे सामने रखा था इसमें सरकार की विकास के सिलसिले में स्ट्रैटजी बतायी गयी है जो फिफथ फाईव ईयर प्लान के लिये है । हमारे विकास की यह स्टैटजी होनी चाहिये कि प्रोडक्टिव ऐम्प्लायमेंट को आगे बढ़ाया जाये । हमारी ऐम्प्लायमेंट ऐसी हो जो प्रोडक्टिव हो । हमारी ऐसी स्टैटजी हो कि लोगों को ऐम्प्लायमेंट भी मिले और प्रोडक्शन भी बढ़े । ऐम्प्लायमेंट भी दो तरह की होती है एक प्रोडक्टिव ओर एक अन-प्रोडक्टिव । हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हम जो ऐम्प्लायमेंट दें वह अनप्रोडक्टिव न हो ताकि देश के जरायों में तरक्की हो सके । हमें रोजगार ऐसे देने चाहिये जिनसे प्रोडक्शन बढ़े और हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वह मुदृढ हो, मजबूत बने । हमारा इस तरफ विशेष ध्यान होना चाहिये । इस समय इस बात की सख्त जरूरत है कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े । आज हरियाणा के अन्दर एक करोड़ से भी कुछ अधिक की आबादी है । अगर ऐम्प्लॉयज स्टेट इश्योरैन्स स्कीम के तहत जो आर्गेनाइज्ड लेबर है, उसका नम्बर लिया जाये तो वह सवा लाख के लगभग है । यह वे लेबरर्स हैं जो ऐम्प्लॉयज स्टेट इश्योरैन्स स्कीम के अन्दर रजिस्टर्ड हैं । अगर अन-रिकोगनाइज्ड लेबर की तादाद ली जाये तो वह दो लाख से भी ऊपर है । यह बह लेबर है जो हरियाणा में प्रोडक्शन के काम करती है और हरियाणा में अन-रिकोगनाइज्ड रहते हुए भी मौजूद है । वह मजदूर हमारे

हरियाणा के अन्दर मौजूद है । हरियाणा को एक करोड़ की मैन पावर में अगर लेबर मैन पावर को लें तो वह दो प्रतिशत तक पहुंचती है । स्पीकर साहब, अगर अपने देश की आबादी को देखते हुए अगर लेबर की एवरेज देखे तो वह डेढ़ परसेन्ट नहीं बैठती लेकिन हरियाणा के अन्दर लेबर मैन पावर दो प्रतिशत बैठती है । इसका मतलब यह है कि हरियाणा के अन्दर प्रोडेक्टिव लेबर, प्रोडेक्टिव मैन पावर बढ़ रही है लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जहां हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और अस्सी प्रतिशत आबादी देहातों में रहती है । इसलिए कारखानों से ज्यादा बिजली के मामले पर, नहरों के मामले पर और खेती के मामलों पर ज्यादा पैसा खर्च करना है । जब हम इन पर ज्यादा खर्च करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आज हमें बिजलीकी सप्लाई ज्यादा चाहिये । अगर हमे एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है तो फ़ैक्टरियों पर कुछ बैलेन्स रखना पड़ेगा । इकोनॉमी के तीन सैक्टर है एक प्राइमरी सैक्टर जिसे एग्रीकल्चर सैक्टर कहते हैं दूसरा सैकंडरी सैक्टर जिसे इंडस्ट्रियल सैक्टर कहते हैं और तीसरा सर्विस सैक्टर । इन तीनों सैक्टरों में आपसी संतुलन, आपसी मेलजोल होना बहुत जरूरी है । चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है अगर यहां पर अन्न की कीमत बढ़ जाती है तो सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं । इंग्लैंड कृषि प्रधान देश नहीं है वह इंडस्ट्रियल कटरी है वहां ऐसा नहीं होता कि अगर अन्न की कीमतें बढ़ जाएं तो दूसरी चीजों को कीमतें भी बढ़ जाएं । लिहाजा अन्न के सिलसिले में हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं

। अन्न के मामले में हम खुशहाल हुए हैं । हम केवल आत्म निर्भर ही नहीं हुए बल्कि हमने अन्न को दूसरे इलाकोंको भी भेजा है । यह हमारी पिछली योजना का एक समावेश है जो पिछले बजट में आया और उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया । उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि एग्रीकलचर सैक्टर को और बजवा वे रहे हैं । इसलिए यह जरूरी है कि जो इंडस्ट्रियल सैक्टर है उसमें भी कुछ बैलेन्स रखा जाए जिसके लिए मेरा एक सुझाव है । जहां फ़ैक्टरियों में बिजली की कटौती की गई है कोई बिजली बन्द नहीं है, बिजली को कमी नहीं है बल्कि 60 प्रतिशत कट की गई है और इसका नतीजा यह है कि जहां पहले दो शिफ्टें चलती थी वहां अब एक शिफ्ट चलेगी जहां पहले एक शिफ्ट चलती थी वहां अब लेबर को ले-आफ करना पड़ेगा । इंडस्ट्रीज को बिजली की मिकदार इस ढंग से तय करनी चाहिए कि लगातार इस वक्त से उनको बिजली मिल सके और मालिक और मजदूर आपस में बैठकर इस ढंग से काम करें कि मजदूरों को कोई दिक्कत न हो । एक बहुत जरूरी चीज जिसके लिए यह सरकार और केन्द्रीय सरकार बहुत जोर दे रही है कि अगर अधिक उत्पादन किया जाए और उसका सही वितरण न किया जाए तो उत्पादन का कोई मतलब नहीं रहता । हमारे देश की प्रधानमन्त्री लगातार कह रही हैं कि देश के अन्दर अधिक उत्पादन करना बहुत जरूरी है । उन्होंने कहा है कि अगर अगली पंच वर्षीय योजना के अन्दर हमको अगम-निर्भर बनना है तो उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है. और उत्पादन के साथ-साथ उसका इक्वीटेबल

डिस्ट्रिब्यूशन भी बहुत जरूरी है नहीं तो अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब और गरीब हो जाएगा । डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होना चाहिए कि जो निचला तबका है उसको सब से ज्यादा वितरण होना चाहिए । अगर हम निचले तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं, देश से गरीबी को हटाना चाहते हैं तो निचले तबके को, गरीबी को ज्यादा चीजों का वितरण किया जाए बजाए इसके कि जो ऊंचे बैठे हैं उनको ही ज्यादा चीजें सप्लाई करें । ऐसा करके ही हम देश के अन्दर से गरीबी को दूर कर सकते हैं । वितरण में यह ख्याल रखा जाना चाहिए और हमारी सरकार का ख्याल इस तरफ है । अगर इस तरह किया जाएगा तो एक अमीर और गरीब के अन्दर जो इन्कम का फर्क है, इम्बेलेन्स है वह खत्म हो जाएगा । मैं तो कहता हूँ कि अमीरों की अमीरी गरीबों में बांट दो और गरीबों की गरीबी अमीरों में गैट दो तो अपने आप ही अमीर गरीब का फर्क मिट जाएगा और गरीब की गरीबी का बटवारा हो जाएगा और अमीर की अमीरी का बंटवारा हो जाएगा । यह लेबर के बारे में एक चीज थी जो मैंने कही है ।

स्पीकर साहब, पिछली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का ओरिजनल प्लान आउट-ले 225 करोड़ रुपए का था जोकि बढ़कर 232 करोड़ रुपए हो गया यानी कि सात करोड़ रुपए हम आगे बढ़ गए । स्पीकर साहब, अगर हम देखें तो 1969-71, 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 हर साल ही हम आगे बढ़े हैं । हम किसी भी सेक्टर, चाहे इरीगेशन सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट

सैक्टर को लें और चाहे लेबर और एम्पलाएमेंट को लें, हम आगे बढ़ है और हमने अपना खर्चा बढ़ाया है । इसका मतलब है कि हर अदारे में काम बढ़ा है, किसी भी अदारे में कमी नहीं रखी हूँ लेकिन होता यह है कि जितना काम बढ़ता है उतनी ही ख्वाहिश बढ़ती है । यह होता है कि अगर आदमी की आमदन बढ़ती है तो उसी अनुपात में उसका खर्च भी बढ़ जाता है । आज बिजली की आमद के मुकाबले खपत दुगनी हे गई है । अगर आज लेबर के वेजिज बढ़ाए जाएं तो प्राईसिज बढ़ जाती हूँ । इसलिए यह जरूरी है कि इन बढ़ती हुई कीमतों को रोकें । जहां तक बजट का सवाल हूँ आमदन के मुकाबले खपत बढ़ी है । इसलिए इस खपत को अपने रिसार्मिज के जरिए अपने साधनों के जरिए पूरा करना है । लेकिन जहां तक इन चीज की प्राईसिज का ताल्लुक है वे लगातार बढ़ती जाती हैं और इसी कारण आज हड़तालें है, लाक आउट्स हैं । इसलिए मंहगाई को रोकना बहुत जरूरी है और इसके बारे में मैंने लेबर ऐडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग मे भी एक सुझाव रखा था कि जितनी भी बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरी हैं वहां हरेक में एर फेयरप्राईस शाप होनी चाहिए और जो छोटी फ़ैक्टरीज हैं उनको पांच-छह को मिलाकर रक फेयर प्राईस शाप होनी चाहिए । आज हमारी मांग ज्यादा पैसे की नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारी मांग कीमतों को रोकने की होनी चाहिए । आज तो हो यह रहा है कि जब भी लेबर को ज्यादा पैसा मिलता है दूसरे ही दिन प्राईसिज बढ़ जाती हैं और उस पैसे का कायदा उतना नहीं होता । लिहाजा महगाई लेना उतना लाभदायक नहीं, जितना कीमत

रोकना है । मैं कह रहा था कि फेयर प्राईस शाप खोली जानी चाहिएं और वहां पर सस्ती चीजें मिले, सस्ता कपडा मिले उन फ़ैक्टरियों के मालिकों को कहा जाए कि दुकान का किराया. दुकान कार खर्चा वे बीयर करें और जरूरत की हर चीज मजदूरों को सही ठीक दार में और सही कीमत पर सप्लाई की जाए । इसका नतीजा यह होगा कि हर मजदूर अपना बजट बनाएगा और वह उन्ही चीजों पर खर्च करेगा जो उसकी जरूरत को चीजें हं ।

स्पीकर साहब, इस प्रकार इसके दाद वे लोग कुछ बचाकर सरकार को देगे । सी ०टी० डी० एकाउंट मे वह पैसे जमा हगे । यह भी एक स्माल सेविंग है और सरकार इस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है और जनता की भलाई के लिये भी यह पैसा खर्च कर सकती है ऐसा कोई अपनाया जाना चाहिये जिससे कीमतें भी एक जगह पर खड़ी रह सकती हे । कीमतो, बढाने के लिये चीजो को दबा लिया जाता है ओर बाजार में तब लाई जाती है जब कीमत को जाती हैं । मैं यमुनानगर में था, नमक नहीं मिलता था, दियासलाई नही मिलती थी और जब बरसात हई तो नमक बाहर निकल आया कि खराब न हो जाए कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां देश में सभी चीजें हैं लेकिन यही पर ऐसे लोग हं कि जो चीजों को दवा कर रख लेते फ़ैब, यही वजह है कि चीजों की कीमतें बढ जाती हैं लेकिन यहां पर कितनी नुक्ताचीनी सुरकार के बारे की जाती है हमने यहां पर देखा कि हमारे कितने भाई ऐसे है जो कि नुक्ताचीनी मे लगे रहते हैं कभी

जनता के हित के लिये, जनता को आगे बढ़ाने के लिये उन्होंने योगदान दिया है? सिवाये इसके कि खड़े होकर बड़े –बड़े भाषण दे दिये और सरकार की खूब नूक्ताचीनी कर दी और कोई तामीरी बात नहीं करते हैं । और हमारे जनसंघ के भाई फिर यह पर मजदूरों को बातें करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, टीचर्स को बात करते हैं, लेकिन जब वे खुद ट्रान्सपोर्ट के मालिक थे, उस समय वहां के मजदूर अपने हितों के लिये सुप्रीम कोर्ट तक गये तो उस समय इन भाईयों के दिलों में मजदूरों के प्रति कोई दर्द नहीं था, अब यह दर्द इनके दिल में उठा हूँ जबकि इनकी प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट्स बन्द कर दी गई है और नेशनलाईज कर दी गई हैं स्पीकर साहब, आज ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाईज कर दिया गया है, और सारे हरियाणा प्रान्त में इलैक्ट्रिसिटी का जाल बिछा दिया गया है और हमारी हरियाणा सरकार ने चप्पे–चप्पे पर सड़के पहुंचा दी है, बसे पहुंचा दी हैं । स्पीकर साहब, इन सब चीजों के करने से बहुत फायदे हुए हैं जब तक यह क़रामत नहीं किये गये थे, तब प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट वाले, जैसे करनाल में तीन प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट्स थी, तक इंडियन करनाल ट्रान्सपोर्ट, करनाल–कैथल द्वारा ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सासाइटीज, करनाल कोऑपरेटिव पापुलर ट्रान्सपोर्ट इन में से एक ट्रान्सपोर्ट वह थी, जिसके एक हिस्सेदार विधायक हमारे जनसंघ के भाई थे एक दफा का जिकर है कि अम्बाला से जगाधरी दा रेल ट्रेफिक प्लड के कारण बिलकुल बन्द हुआ पड़ा था । लोग बसों के द्वारा जा रहे थे तो मैं और एक करनाल कोऑपरेटिव ट्रान्सपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर

सरदार नक्षत्र सिंह उसी वस में सफर कर रहे थे, बस खचाखच भरी पड़ी थी, तो उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया कि सभी सवारियों से पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लिये। यह तो इन का रुतबा था सारी टिकटों के पैसे खा गये, गवर्नमेन्ट का टैक्स भी खा गये, इसलिये इनको सरकार की इस नशनलाईजेशन से दर्द हो रहा है, और किसी बात से किसी मजदूर के नाम से कोई दर्द नहीं हो रहा है स्पीकर साहब, मैं क्या बताऊं, उस समद प्राइवेट की हालत थी एक दूसरे की पिस्तौल लेकर कतल करने की कोशिश करते थे। इन लोगो तो इसलिए दर्द हो रहा है यह सारे पैसे अब उनकी जेबी में नहीं जा सकते। लेकिन जब से ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाईजेशन हो चुका है लोगो को बड़ा आराम हो गया है पब्लिक बड़े आराम से से चल फिर सकती है, किसी किस्म की लोगो को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रात को ट्रान्सपोर्ट के चालू करने का सपीकर साहब यह भी एक प्रतीक है कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन जो है, वह काबिले तारीफ है। आप अपनी प्राइवेट कारों भी रात के वक्त जहां मजी चाहे हरियाणा में ले जा सकते हैं आप पडौसी स्टेट्स को ही देख लिये कि वहां पर ला एण्ड आर्डर की क्या हालत है। लेकिन एक हरियाणा ही एक ऐसा प्रान्त है कि जहां कोई डकैती नहीं चोरी नहीं कतल नहीं, मतलब कि पब्लिक को हर तरह से आराम है और ऐसा तभी हो सकता है कि जब किसी प्रान्त को ला एण्ड आर्डर की स्थिति सदृढ हो। ला एण्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिये हमारी पुलिस के पास वायरलैस

सैटस दिये गये, जगह जगह पर टेली फोन वगैरह दिये गये ताकि अपराधो को रोका जा सके और ऐसी स्थिति हरियाणा प्रान्त में है भी लेकिन यहां परं यह कहा जाता है कि यू ही पुलिस के ऊपर इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है, भाई चश्मा बदल करके देखा करो जिनकी आखो में पीलिया हो तो उनको तो हर चीज पीली ही पीली नजर आएगी । अगर पुलिस से हर तरह की फ़ैसिलटीज न दी जाएं तो ता एरण्ड आर्डर केसे रह सकता है । स्पीकर साहब दूसरा आज प्रोडक्टिव अदायरो मे पैसा खर्च किया जाता है जिसकी हमें जरूरत है जैसे टूरिजम वगैरह । इस से हमारे हरियाणा की तरक्की के बारे रोशनी पड़ती है । हमारे हरियाणा में जब बाहर की कमेटिये के मैम्बर साहबान आते है जैसे पिछले दिनों यहां पर केरल से रिसीर्सिज कमेटी आई, बेदाकिस्मती से उस कमेटी कै चेयरमैन चौधरी चांद राम थे, वह वहां पर सिर झुकाकर बैठे रहे, उनको बात नहीं आई । अगर चौधरी सुरजीत सिंह मान, कैप्टन सीस राम जी जैसे वहां न होते तो हमारे हरियाणा प्रान्त की इज्जत डूब जाती तो आप देखिये कि ये कर क्या सकते हैं, यह लोग तो असम्बली के अन्दर बोल सकते है कि फलां जगह यह हो गया, फलां जगह सरकार ने यह कर दिया, केवल नुक्ताचीनी ही कर सकते हैं । चौधरी चांद राम जी तो बबैन से मुश्किल से कुछ वोटों से जीत कर आये है, अगर डा० ओम प्रकाश साहब के बहनोई इनकी मदद न करते तो आज यह यहां पर न होते

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है! जोशी साहब ने जैसे फरमाया चौधरी चांद राम जी रिसोर्सिज कमेटी के चेयरमैन थे, रिसोर्सिज कमेटी के चेयरमैन तो का गुलाब सिंह जैन हैं, वह तो एशोरंन्स कमेटी के चेयरमैन हैं, यह गलत कह रहे हैं

Mr. Speaker : This is no point of order, This is People of information

Shri Chander Joshi : I meant the 'Assurance committee.

In correct myself. तो मैं कह रहा था कि यह हालात आज हमारे देश के अन्दर है । हमररे ओपोजिशन के भाई कहते हैं कि सेविंग धक्के से करवाई जाती है, टीचरों के मामलो मे उनको पता ही नही है जैसे हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट में जो रिसोर्सिज बताये है, उनके स्माल सेविग भी एक सोर्स बताया गया है और अपिको यह सुन कर खुशी होगी कि हमारे देहाती हल्का के लोगो ने भी इसमे बढ-चढ कर भाग लिया है और दूसरी तरफ हमारा मजदूर अदारा क्या, गवर्नमेंट सर्वेन्टस क्या, सभी ने मिलकर इस सेविंग में योगदान दिया है टीचरो की बात कर रहा था जब तक इस समाल सेविग में टीचरों का तीन करोड से ऊपर रुपया जमा है, जी०पी० एफ ० में भी तीन करोड से उपर पैसा जमा है तो यह सब समाल सेविग ही तो है जिसको गवर्नमेट

भलाई के कामों के लिए यूज कर सकती है । यह उन्हीं टीचरों की ही कमाल है, जिनके बारे में हमारे यहां आपोजीशन के भाई बातें करते हैं कि टीचरों के साथ बड़ा धक्का हो रहा है टीचरों को यू ही गुमराह किया जाता है और वे लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो टीचरों को यूही गुमराह करते हैं और वे तब तक यहां पर बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें ऐसा करने का मौका मिलता रहेगा लिहाजा मैं कह सकता हूं कि हमारे टीचर्स बहुत समझदार हैं, हमारे एम्प्लॉयर्स बहुत समझदार हैं वे अब इन लोगों के बहकावे में नहीं आ सकते आकर साहब, टीचर्स के बारे में एक । और यहां पर कहूंगा कि इस समय टीचरों को जो गवर्नमेंट की तरफ से आने जाने में सहूलियतें दी हुई हैं उनको महीने में 40 सिंगल फेयर आने-जाने के लिये देने पड़ते हैं मैं यह चाहता हूं । कि 40 की बजाए उन्हें 30 सिंगल फेयर देने पड़े तो ठीक रहेगा ताकि उनकी और थोड़ी सी बचत हो सके । दूसरी बात जो टीचर्स के लिए हरियाणा सरकार ने की है वह है कि उनको अपने हिस्ट्रिकल पर रखा है लेकिन कईयों को गांवों में रखा गया है और शहरों में साढ़े सात से साढ़े बारह परसेंट का उन्हें अलाउंस दिया जाता है, मेरी सरकार से पुरजोर दरखास्त है कि अगर यह चीज में भी कर दी जाए और देहाती में नौकरी करने वाले टीचर्स को यह इनसैटिव हो तो वे लोग जो देहाती में जाने से कतराते हैं, वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे । दूसरी बात है कि आज जो टीचर्स का डी 0ए 0 कट किया जा रहा है उसको रेस्टोर किया जाए, इस सारी बात को एग्जामिन किया जाए, बेशक उन्हें

यह नकद पैसे न दिए जाए उनके जी० पी० ० फण्ड में जमा हो जाएं और बाद में सरकार इन पैसे को अपने इस्तेमाल में ला सकती है, कम से कम यह होना चाहिए । इससे आगे चलकर मैं एक बात और कहूंगा कि रोडवेज एम्पलाइज, टीचर्स, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स वगैरह जो हैं, इन लोगों की जो अलग-अलग यूनियन्ज बनी हुई हैं इनकी एक प्वायंट मैनेजमेंट कौन्सिल बनाई जाए, उसके चेयरमैन बेशक चीफमिनिस्टर साहब हों, ऐसा करने से आपस में ताल-मेल रहेगा और आगे के लिए दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं होगी इस से ऐसा होगा कि और को भी, चाहे हमारे रोडवेज के कर्मचारी हों, एम्पलाइज हों, या कोई तबके के लोग हो, गुमराह करने का मौका नहीं मिलेगा यह मैं चाहता हूँ कि प्वायंट मैनेजमेंट कौंसिल जिमको इंग्लैंड में ब्हाइटले कौंसिल कर। जाता है उसकी स्थापना की जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है मैं अपने टीचरों रुपए और मुलाजमों को मुबारिकबाद देता हूँ कि वे बड़े शांत ढंग से अपना काम कर रहे हैं । इसके विपरीत हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में आपको पता है कि कितनी जद्दोजहद और परेशानी हो रही है इसलिये मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह अपने मुलाजमों को जायज मांगों की तरफ जल्द से जल्द गौर करे । अगर सरकार जल्दी कोई माकूल फैसला करेगी तो इसमें हमारी भी भलाई होगी और मुलाजमों की भी भलाई होगी । ऐसा करने के लिए सरकार से मेरी मांग भी है और अपील भी है । लेबर के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में कहा गया कि उसमें बैलेंस लाने की

जरूरत है यहां पर कहा गया कि फरीदाबाद में यह हो गया, वह हो गया यह भी कहा गया कि वहाँ पर एक लाख मजदूर बेकार हो गये हैं मैं अपने भाइयों को बतलाना चाहता हूँ कि फरीदाबाद के अन्दर 65,000 से ज्यादा मजदूर नहीं है और वहाँ पर 440 से कापर फैक्ट्रियां हैं सारे हरियाणा है अन्दर 1,25,000 आर्गेनाइज्ड लेबर है तो अकेले फरीदाबाद में एक लाख कैसे हो सकती है अगर मजदूरों में आपसी तालमेल करने का तरीका हो तो उनको कम कष्ट हो सकता है इसके साथ ही मैं लेबर कोर्ट के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ दो लेबर कोर्ट हुआ करती थी लेकिन मिस्टर टुकराल के रिटायर होने के बाद यहाँ सिर्फ एक ही लेबर कोर्ट रह गई है । उसमें मिस्टर शर्मा है जो कि हाट के पेशियेन्ट है उनसे अकेले से इतना काम नहीं हो सकता इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक और लेबर कोर्ट खोली जाए ताकि मजदूरी और मालिकों का तालमेल ठीक ढंग से रह सके (इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई) आज अगर मजदूरों के साथ ठीक समय के अन्दर अन्दर न्याय हो तो देश में और उनमें यह एक जागरूकता की भी निशानी है मैं चाहता हूँ कि मालिक और मजदूरों के संबंध आज और माडर्नाइज्ड होने चाहिये । आजकल के माहौल में हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र और जनता के हित को देखना चाहिये । देश में आज अगर आर्गेनाइज्ड लेबर की तादाद एक या दो परसेंट है और वह अपने हकों को लेकर स्ट्राइक करना चाहते हों और दूसरी तरफ 98 परसेंट लोग जो हैं वह उन्हें एट-बे नहीं रख सकते तो उस वख्त

उन्हें भी यह सोचना चाहिये कि इन 98 परसैट का हित भी हमारे साथ है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं लाक-आउट और स्ट्राइक के टोटली खिलाफ हूँ और इनको बन्द कर दिया जाए, यह भी ठीक नहीं है । मैं तो यह चाहता हूँ कि ऐसा तालमेल बनना चाहिये कि लेबर झगड़ा करने कीर बजाए अपने नैशनल हित को सोचे । लेबर का हित भी इसी में है और सरकार का हित भी इसी में है, ऐसा करने से दोनों काँ भलाई होगी । इन शब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यह जो अनुमान और बजट हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में पेश किया, उनका मैं अनुमोदन करता हूँ ।

श्री धजा राम (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को बोलने का टाइम दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले तीन रोज से बजट पर डिस्कशन हो रही है कुछ भाइयों ने इस पर अपने कन्सट्रक्टिव सुझाव रखे और कुछेक हमारे आपोजीशन के दोस्तों ने डिस्ट्रक्टिव सुझाव रखे । ठीक है, ये हमारे अपोजीशन के भाई अपनी आदत से लाचार हैं । इनको ऐसी वात करना नहीं चाहिये थी लेकिन जैसा यह कहते हैं ठीक है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसे पहले कि मैं बजट पर बोलूँ, सबसे पहले मैं इन भाइयों को यह बताना चाहता हूँ कि आजादी से पहले हिन्दुस्तान में आजादी के लिये कितनी कुरबानी दी गई यह सब लोगों के सामने हूँ । 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान आजाद

हुआ । हर शहरी ने यह सोचा कि हम आगे बढेगे, तुम तरक्क्याई करेगे । इसमें कोई शक नही है हिन्दुस्तान मे काफी तरक्की हुई, यह सब लोगो के सामने हे और इसे डिटेल मे बताने की जरूरत नही है । लेकिन हमारा हिन्दी स्पीकिंग एरिया या मौजूदा हरियाणा की वात मै करनां चाहता हूं । हमारी यह वदकिस्मती रही कि प्वांयट पंजाब में हर लिहाज से हम इग्नोर किये जाते रहे चाहे इडस्टरी ले लो, डिवैल्पमेंट लेलो, एजुकेशन ले लो रोड ट्रांसपोर्ट ले लो यानी हर तरह से हमें इग्नोर किया जाता रहा लेकिन आज हमारी पोजीशन यह है कि हमने इन सब अदायरे मे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की है । उन दिनों 'मे चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर आया, चाहे सच्चर साहब की वजारत आई, चाहे भार्गव साहब की आई, चाहे कैरों साहब की जाई और चाहे कामरेड रामकिशन की वजारत आई, ये भाई उन दिनों ट्रैंजरी बेंचिज परं बैठते थे, यानी सरकार के साथ होते थे लेकिन इनमे यह हिम्मत नही होती थी कि मौजूदा हरियाणा में डिवैल्पमेंट के कामों के लिये मागं करें । लेकिन आज ये इस सरकार को क्रिटिंसाइज करते है । ठीक है, करने दो, यह इनकी आदत है ।

1 नवम्बर, 1966 को जब हरियाणा' वजूद में आया तो उसवक्त पंडित भगवत दयाल 'जी चीफ मिनिस्टर बने और उनको' मिनिस्टरी में चौधरी दल सिंह जी भी 'मिनिस्टर थे' । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा में इस भाई से पूछना चाहता हूं कि इन्होने अपनी वजारत के अन्दर क्यों किया मैं आपको बताना चाहता हू कि कि जिसे वक्त हरियाणा बना तो—हमारे देश 'के के अर्थ—शास्त्री थे

उनका यह ख्याल था कि हरियाणा एक छोटी सी स्टेट है और इसके पास कोई सोर्स आफ इंकम नहीं है इसलिये हरियाणा तरक्की नहीं कर सकेगा, हरियाणी आगे नहीं बढ़ सकेगा और ऊपर नहीं उठे सकेगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हुआ भी ऐसा ही कि डेढ साल तक हमारी यह बदकिस्मती रही कि हरियाणा । में डिवैल्पमेंट का कोई भी काम नहीं हुआ और वहां फिरकापरंस्ती की बातें चलती रही । इसके इलावा हरियाणा कर लीडर शिप ऐसे लोगों के हाथों में आई जोकि तंगदिल से बात करते थे और जनता को गुमराह करते थे । इसलिए मैं इन भाइयों से पूछना चाहताहूँ कि ये उस वक्त सरकार में शामिल थे, इन्होंने हरियाणा प्रान्त के लिये जो हरियाणा की डिवैल्पमेंट के लिए क्या किया 1967 में हरियाणा में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें कि कांग्रेस के 48 एम 0 एल 0 एज0 बने । मिनिस्टरी बनने के बाद 13 दिन बाद सरकार टूट गई । उसके बाद राव बीरेन्द सिंह जी की सरकार बनी और वह भी 8- 9 महीने बाद टूट गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि डेढ साल तक हरियाणा में कोई भी काम नहीं हुआ । मई 1968 के बाद जब चौधरी बसी लाल जी इस प्रदेश, के मुख्य मंत्री बने तब असली मायनो में हरियाणा के अन्दर काम हुए और जो आप लोगों के सामने हैं । इसमें कोई शक नहीं कि इनके टाइम में हरियाणा की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है । इसी वजह से आज हरियाणा का नाम केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है । हरियाणा आज हिन्दुस्तान के नक्शे पर सब से पहली स्टेट है जिसने कि इतने टाइम में

इतनी तरक्की की । अपोजीशन के भाइयों ने एक बात रखी कि हरियाणा में कुछ नहीं हुआ, हरियाणा में नहरें नहीं निकल रही हैं । मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आज हरियाणा में कितने काम हुए हैं? आज इरीगेशन को ले लीजिये । इन्दिरा गांधी कैनल बनी, चक्रवर्ती कैनल बनी, झज्जर लिस्ट स्कीम बनी, हांसी ब्रांच पक्की बनी, सुदर. ब्रान्च पक्की बनी और भालोट ब्रांच पक्की बनी । इन सब नहरों को पक्का किया जा रहा है और अब किसानों को पहले से डेढ़ गुना पानी दिया जा रहा है । इतना कुछ होने के बावजूद भी ये भाई कैसे कह सकते हैं इरीगेशन के काम में तरक्की नहीं हुई? इसके अलावा मैं इनको बतानी चाहता हूँ कि जिस वक्त हरियाणा बना उस वक्त हरियाणा में केवल 27,000 ट्यूबवैल्ज थे और आज 1,23,000 ट्यूबवैल्ज हैं । सरकार ने किसानों को ट्यूबवैल्ज लगाने के लिये फैसेलिटी दी है और भी दी जा रही है । मेरा कहने का मतलब यह है कि चौधरी बसी लाल की रहनुमाई में हरियाणा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है अब मैं अपने हल्के के बारे में कुछेक बातें कहना चाहता हूँ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे हल्के के साथ से एक जोशी ड्रेन निकलती है । हर साल इसमें ओवर-फलो और ब्रीचिज होने की वजह से वह आटा, टीटो खेड़ी और कर सिन्धु इन तीनों गांवों की लाखों रुपये की फगल बर्बाद होती है डिप्टी स्पीकर साहिबा. मैं आपके जरिये सरकार से यह सुझाव देना चाहता हूँ कि वहां पर एक -डेढ़ -दो मील की छोटी ड्रेन निकाली जाए और उसे

इन्दिरा गांधी कैनल में डाला जाए ताकि हर साल जो लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं वे अपनी फसलें बचा सकें ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा अब मैं अपने हलके की रोडज के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं । मेरे हलके में जामनी से पीलूखेडा मंत्री तक का लगभग डेढ़ मील सडक का टुकड़ा बनाया जाना निहायत जरूरी है क्योंकि इस वक्त अगर हम जामनी से पीलू खेडा मंत्री जाएं तो वाया जींद जाना पड़ता है जिस में तकरीबन 40 मील का चक्कर पड़ता है और जिला करनाल के जो गांव जींद डिस्ट्रिक्ट में आए हैं जैसे गांगट हेडी, पोपडा व रटौली से जामनी तक सडक बन चुकी है । इस लिए इन गांवों का पीलू खेडा मंडी से लिंक बनाने के लिए भी वह टुकड़ा बनाया जाना निहायत जरूरी है इस के इलावा टोटो खेडी में बरडौद बरडौद से खातला, और खातला से मुसलाना की सडके भी बनाई जानी बहुत जरूरी है । इसी तरह से एक दौर सडक सफीदों । से डडवाडा गांव तक वाया निमनाबाद, हाट से अचरा खुर्द ओर अंचरा खुर्द से अंचरा कलां तक अगर सडक बना दी जाए तो सफीदो से गोहाना जाने के लिये बहुत छोटा रास्ता बन जाता है और इस के बनने से लोगों को बहुत सुविधा होगी । इस लिए मे निवेदन करूंगा कि सरकार इन सडकों को बनाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रबंध करे ।

हमारे वित्त मंत्री साहब ने यह बजट बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है इस में कोई शकोशुबा की बात नहीं है । उन्होंने हर

डिपार्टमेंट के लिए बजट में फण्ड्स प्रोवाइड किए हैं चाहे वह एजुकेशन का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे इन्डस्ट्री का हो मेरा कहने का मतलब यह है बजट बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है । चौधरी दल सिंह जी ने यहां पर कहा कि खेती के बारे में हरियाणा में कोई तरक्की नहीं हुई ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1966 में जब हरियाणा बना था उस समय एकरू लाख टन अनाज हरियाणा सैट्रल दल से लेता था लेकिन आज 12 लाख टन हम सैट्रल पूल में दे रहे हैं । इस लिए मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो हम इतना सरप्लस अनाज पैदा करके सैट्रल पूल में भेजते हैं इस से बड़ा तरक्की का सबूत और क्या हो सकता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि उन्होंने बिलकुल बेबुनियाद नुक्ताचीनी की है । इस के इलावा उन्होंने हरिजनों के बारे में कहा कि उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा । मुझे मालूम नहीं कि वे कब से हरिजनों की भलाई चाहने लगे हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन के खुद के गांव की बात है कि यह अपने जिस आदमी को सरंपच बनाना चाहते थे उसको वहां के हरिजन वोट नहीं देना चाहते थे । वहां झगड़ा भी हुआ था जिस में कि इन के आदमियों को भी चोटें आई थी और केस भी रजिस्टर हुआ था । हरिजन चूंकि चौधरी दल सिंह के आदमी को वोटें देना नहीं मानते थे इसलिए इन्होंने उनका शामलात में और खेको में जाना बंद कर दिया ओर वे बेचारे 10/15 दिन तक अपने अन्दर ही टट्टी पेशाब करते रहे । जब हरिजनों के साथ यह ऐसा सलूक करते रहे हैं तो आज यहां पर उनकी हमदर्दी का कैसे

दम भरते हैं । मैं समझता हूँ कि यह मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है वरना इनको हरिजनों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है हमारी सरकार ने इस बजट में हरिजनों को फ़ैसिलीटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन किया है और जो हरिजन निगम है उस के जरिए इन को हर प्रकार के लोन दिये जाते हैं और पांच साला एलान में 10 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा

चौधरी पीर चन्द : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिबा इन्होंने मालूम होता है बजट को पढ़ा नहीं वैसे ही 10 करोड़ रुपया कह दिया है ।

Deputy Speaker : Please take your seat. This is no point of order.

श्री धजा राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं निवेदन कर रहा था कि हरिजनो के लिए इस बजट में काफी फण्डज प्रोवाइड किए गए हैं अब मैं चन्द बाते को—आपरेटिव सोसाइटीजके बारे में कहना चाहता हूँ । कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिए लोगों की बड़ी तरक्की हुई है, जो छोटा कहना था, गरीब हरिजन था और जो मजदूर लोग थे उन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटीया बना—बना कर ऊपर उठने की कोशिश की बै हमारी सरकार ने इस के लिए भी बजट में काफी फण्डज प्रोवाइड किए हैं । यहां पर चौधरी दल सिंह ने अपनी तकरीर करते वक्त कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को बोगस लोन दिए जाते हैं । मैं उन से यह बात पूछना चाहता हूँ कि यह सब टैक्टिक्स सिखाए हुए किस के हैं मेरा खयाल है

जिन्होंने यह टैक्टिक्स अपनाया । मैं आप को एक मिसाल देता हूँ इन की 'दी राम राए बिक क्लिन सोसाइटी' पहले राम राए में थी उस को वहाँ से इन्होंने गवर्नमेंट को परमिशन के बगैर जीद शिफ्ट किया और उस के बाद जीद से बिशनपुरा में जोकि रोहतक रोड पर थी फिर शिफ्ट किया गया और वह भी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर । इस तरह इरैगुलेरिटी करने के आधार पर उस का लाइसेंस कैसिल हुआ और डिप्टी स्पीकर साहिबा इस सोसाइटी में जो कार्यवाही वगैरा की गई वह सारी बोगस है । उस सोसाइटी में, चौधरी दल सिंह, शायद इनके परिवार का मेंबर भी उस में कोई हो और एक आधा कोई दूसरा मेंबर, कई बार इस के मेंबर बनते रहे और कई बार निकलते रहे । तो फिर यहमेरी समझ में नहीं आ सका कि

गवर्नर एर्डस पर बोलते हुए उन्होंने यह कैसे कह दिया कि मेरा कोई भट्टा नहीं हं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यही नहीं इन्होंने स्टेट बैंक आफ पटियाला से आन बीहाफ आफदी सोसाइटी रुपए ड्रा किए । मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर उन्होंने यह रुपया बैंक से ड्रा किया था । मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, उनको इस बात के लिए चौलेंज करता हूँ वह उस सोसाइटी के रिकार्ड को हाउस में पेश करें और अगर यहां नहीं तो हाउस से बाहिर उस को एग्जामिन करवा लिया जाए, उस में चौधरी दल सिंह ने खुद अपने पांव के अंगूठे लगा रखे हैं और वह सारी बोगस कार्यवाही है । उस रिकार्ड को देख का सब कुछ

पता चल जाएगा कि यह कितने ईमानदार हैं । इस के बाद मैं ला एंड ऑर्डर की तरफ आता हूं डिप्टी स्पीकर साहिबा ला एंड आर्डर हरियाणा में बहुत अच्छा है इस में कोई शकोशुबा की बात नहीं है हमारी दूसरी जो नेबरिंग स्टेट्स है, यू ० पी ० है, राजस्थान है, पंजाब है, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा वगैरा जो हैं, वहां कोई न कोई आन्दोलन चलता ही रहता है और गड़बड़ रहती है । लेकिन हमारे यहां कोई इस किस्म की बात नहीं दिखाई देती और अगर मैं कहूं कि हमारी स्टेट से क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन किसी और स्टेट की नहीं है तो गलत न होगा डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा बनने से पहले खामी गांव से जब मुजारों को उजाड़ा गया उस वक्त वह भाई सरकार के साथ था । मैं उन से पुछना चाहता हूं कि क्या उस समय उन्होंने सरदार प्रताप सिंह कैरो, पंडित नेहरू या गवर्नर साहब को इस बात के लिए एप्रोच किया था कि उन गरीब मुजारों को न उजाड़ा जाए । उस समय उनका ला एंड आर्डर कहा गया था और मुझे समझ नहीं आता आज वह ला एंड आर्डर सी बात कैसे कहते हैं, और हरिजनों और मुजारों की हमदर्दी की बात कैसे करते हैं फिर उन्होंने कहा कि जींद डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा चोरियां होती हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा चोरियां तो सब जगह होती हैं लेकिन जींद में जो चोरिया होती हैं उन में चौधरी दल सिंह का हाथ कुछ जरूर है । जींद के पास एक राजपुरा गांव में बिजली की मोटर चुराई गई उस का दो महीनों तक इन्होंने केस रजिस्टर नहीं होने दिया लेकिन उस के बाद वह लोग एस० पी ० वगैरा को मिले तो उनका केस रजिस्टर हुआ और फिर वह केस सी ०आई

0 ए 0 वालों को दिया गया और उन्होंने चोर को पकड़ लिया और जब उस के खिलाफ केस रजिस्टर होने लगा तो चौधरी दल सिंह पर्सनली गए और यह कह कर केस फाईल करवा दिया कि गांव में पाटीबाजी है इसलिए चोरी उस के नाम लगाई गई है । अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि चोर पकड़ा जाने पर भी इन्होंने उसके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होने दिया तो इस से साफ जाहिर है कि उस के पीछे इनका हाथ था ।

Deputy Speaker : No personal remarks please, otherwise, he will demand time for personal explanation from me.

श्री धजा राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ला एंड आर्डर के बारे में बोल रहा हूँ । ला एंड आर्डर हरियाणा का बहुत अच्छा है, इम में कोई शकोशुबा की बात नहीं है । मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और यह बात 1952 की है । उस वक्त चौधरी दल सिंह जी एम 0 एल 0 ए 0 हुआ करते थे इनके गांव में एक अध्यापिका पढाया करती थी । उसको इन्होंने कैसे जबरदस्ती अपने घर में रखा है यह बात हाउस में बताते हुये मुझे शर्म आती है । जो आदमी खुद इस तरह की हरकतें करता हो वह अगर ला एंड आर्डर के खराब होने की बात करे तो यह अफसोस की बात है...

Deputy Speaker : I would again request the hon. Member that he should not go personal, otherwise he will demand time for personal explanation from me.

श्री धजा राम : हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस के सामने एक सुझाव रखा और बताया कि सरकार हर जिला हैडक्वार्टर पर और सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर पर धर्मशाला बनाना चाहती है । यह बहुत अच्छी बात है जो सरकार करने जा रही है और इस में शक नहीं कि हर आदमी को इन में ठहरने की जगह मिलेगी लोकिन जींद के बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर वहां पर कोई धर्मशाला बनायें तो उसका इन्तजाम सरकार को सकती से अपने हाथ में रखना चाहिए क्योंकि चौधरी दल सिंह को धर्मशालाओं पर कमा करने की बड़ी आदत है । इनके गांव राम राये में करसिंधू के बणिये ने धर्मशाला बनवाई थी लेकिन चौधरी दल सिंह ने उस पर कक्का करके अपनी आटे की मशीन लगा ली और आज भी इन के परिवार का कब्जा है । तो मैं अर्ज करता हूँ कि जींद धर्मशाला बनाई जाये तो उसका इन्तजाम जरा सख्ती से होना चाहिए कही ऐसा न हो कि वह उस पर कब्जा जमा लें क्योंकि कब्जा करने में वह बहुत तगडे है,कभी जमीनों पर कब्जा तो कभी धर्मशालाओ पर कब्जा कर लेते हैं.....

Deputy Speaker : No personal remarks please.

Shri Amar Singh : On a point of order, Madam. The hon. Member against whom personal remarks are being made, is not present in the House. और रुह रिमार्कस भी ऐसे हैं जो शोभा वाली बात नहीं है । अगर हाउस क्षा तैयार इस तरह का हो गया किए एक मैंबर दूसरे मैंबर के बारे में ऐसे रिमार्कस करेगा तो

इससे हाउस की शोभा नहीं बढेगी अरि यह मामला और आगे बढेगा ।

Deputy Speaker : Order please. I have already requested the Member that he should not go personal.

Chaudhri Partap Singh Daulta : And, whatever has been utter against him should be expunged,

श्री धजा राम : मे तो सच्चाई बता रहा हू अगर इसे' भी महसूस करते हैं तो ठीक है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ला एंड आर्डर की बात कर रहा था और सच्चाई बता रहा था । एक बात और कहना चाहता हूं कि लाइफ में तीन स्वाद होते हैं । दुनिया मे चाहे पालिटिक्स मे कह लो या दूसरी आम लाईफ में भी कहे लो । एक तो खुजली का स्वाद दूसरे ब्याज का स्वाद, और तीसरे राज का स्वाद और यह तीनों बहुत खतरनाक बीमारियां और स्वाद है । जब आदमी खुजली करता है तो उसे बहुत स्वाद आज है मीठा मीठा और जब तक खून न निकल आये वह खुजली करने से रुकता नहीं है । दूसरी है ब्याज की बीमारी और स्वाद जो आदमी ब्याज पर रुपया देता है वह न कोई दूसरा बिजनैस कर सकता है, न अपने बच्चो को हायर एजुकेशन दे सकता है और न अपना रिर्गवेग स्टैंडर्ड ऊपर उठा सकता है बस ब्याज में पैसा लगा कर ही स्वाद लेता रहता है । तीसरा स्वाद या बीमारी है राज की जो कि बहुत ही खतरनाक है । चौधरी दल सिंह चार

महीने स्टोर 13 दिन वजारत की कुर्सी पर बैठे हैं इसालिए उन को हर वक्त उसी कुर्सी के ही खाब आते रहते हैं ।

Deputy Speaker ; Please address to the Chair. Also, please do be-personal.

श्री धजा राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह भाई जिस वक्त ताकत में आये तो उस वक्त तो कुछ किया नहीं लेकिन आज यह बातें करते हैं कि हरियाणा में कुछ हुआ ही नहीं है । मैं उन से कहूंगा कि अगर उनके दिमाग में फर्क है तो उस भाई को अमृतसर जा कर अपना दिमाग ठीक करवा लेना चाहिये । आज सारा भारत जनता है कि हरियाणा ने कितनी तरक्की की हैं और सारे देश में हरियाणा की तारीफ ढो रही है । हमे इस बात पर बहुत फख सै कि हमें इतना तगडा और मजबूत चीफ मिनिस्टर मिला है कि जिसकी रहनुमाई में हरियाणा तरक्की कर रहा है । चौधरी दल सिंह ने जिला जींद के कुछ गांव का जिंकर किया कि वहां पर उन गांव मे पानी नहीं मिल रहा है । मैं मानता हूं कि बडौदी, रूपगढ, कैरखेडी, अहीरका, झाजकला, झाज खुर्द, दरियावाला, खेडीजाजो और गांवों वाजवान में पानी वारा दे और नहर का पानी भी वाम लगता है । अगर सामदो माइनर को चार बुरजी तक ऐक्सटैंड कर दिया जाये तो उन सभी गांवों को पानी मिल सकता है । लोकिन मैं हैरान हूं कि चौधरी दल सिंह को अब उन गांव का कैसे ख्याल आ गया जब पावर में थे तो कभी उन्होंने उन गांवों के बारे में नहीं सोचा

। 1972 के बाद सब से पहले उन्होंने इन गांवों के बारे में सोचा और नारा लगाया कि उन गांवों में पानी खारा हूँ । इसकी क्या वजह है वह मैं बताता हूँ । दरअसल बात यह है कि इन्होंने कैरखैडी गांव में जमीन ले रखी है और यह गांव इन गांवों के साथ लगता है । उन को इन गांवों के बारे में इन्ट्रेस्ट यह है कि अगर इन गांवों को पानी मिल गया तो इस गांव में इनकी जमीन को और ज्यादा पानी मिल जायेगा । उन्होंने वहा ट्यूबवैल भी लगा रखा है लेकिन हर एक आदमी चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी चीज मिले और चौधरी दल सिंह तो हर चीज अच्छी और ज्यादा अपने लिये चाहते हैं । (विघन)... हर आदमी अच्छी चीज पसंद करता है (हंसी)..

Deputy Speaker ; Again personal. These words may be expunged from the proceedings.

श्री छजा राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं गुजारिश कर रखा था कि इन गांव को वाकई पानी की तकलीफ है और वहां पर पानी देने को बहुत जरूरत है क्योंकि वहां पर पानी बीज अच्छी है ओर लोग खुद वहां बोरिंग करवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पानी बहुत गहरा है । इसलिये मेरा सरकार से सुझाव है एक वहां एर रिंग मशीनों से गहराई तक खुदाई करवा कर सरकारी तौर पर ट्यूबवैल्ज लगाये जाये और इस तरह से लोगों को पानी दिया जाये । अन्त में अब आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने बोलने के लिये मुझे टाईम दिया है ।

राव दलीप सिंह (कनीना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया । हरियाणा प्रांत एक छोटा सा प्रदेश है और इसकी आबादी ज्यादातर किसानों काशतकारों की है जो कि तकरीबन 85 फीसदी है । यहां का किसान भी बहुत मेहनती और ईमानदार है । यहां का किसान इतना मेहनती है कि दिन रात खेत में काम करता है, उसकी औरत काम साथ करती यूँ और बच्चे काम करते हैं । मैंने बजट में देखा है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सैक्टर में 985 लाख रुपया रखा गया है और इरीगेशन एंड पावर के लिये 4,613 लाख रुपया खर्च के लिये रखा है मैं इस बात को देख कर बहुत खुश हूँ कि एग्रीकल्चर और इरीगेशन के लिये जो खर्च रखा गया है वह किसी हद तक ठीक ही रखा गया है होना तो यह इससे भी ज्यादा चाहिये था लेकिन फिर भी आबादी के प्रोपोर्शन को देखते हुए यह खर्च जो इन मदों के लिये रखा गया है किसी हद तक ठीक है और मैं इस के लिये सरकार की सराहना करता हूँ कि यह सरकार चाहती है कि हरियाणा का किसान ऊपर उठे और उसका स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा हो । इसके साथ-साथ इस में यह भी ध्यान म्बा गया है कि जो बैकवरे एरियाज हैं जहां पहले से ही पीने का पानी नहीं मिलता आया है, जहां पर आने-जाने के साधन। रोडज के नहीं है और हर लिहाज से वह पिछड़े हुये है पहले तो पंजाब में सारा हरियाणा ही बैकवर्ड रहा लेकिन अब भी हरियाणा में ऐ से अलाके है जो बैकवर्ड हैं, उनको राहत दी जाये सरकार ने जो अब उन बैकवर्ड अलाको काँ तरफ ध्यान दिया है मैं

उसकी सराहना करता हूँ और इस बात की तारीफ करता हूँ कि सरकार के दिमाग में यह बात है कि रीजनल इम्बैलेंसिज को दूर किया जाये और ऐसा करने की कोशिश की भी दे इसको दूर करने की कोशिश की गई, मैं इस बात का तहेदिल से शुक्र गुजार हूँ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज किसान को बिजली की जरूरत है पानी की जरूरत है । जहां तक मेरे जिले का सवाल है मैं अपने जिले का नाम इस लिए नहीं लेता कि मैं इससे ताल्लुक रखता हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक मैम्बर, हर एक आदमी जो हरियाणा प्रान्त का रहने वाला है, अगर वह सही मायनों में अपने आपको इन्सान कहलाने का हकदार है तो उसको जरूर महसूस करना चाहिए कि जो बैकवर्ड इलाके हैं, जिनको बिजली और पानी की बहुत जरूरत है उन को सबसे पहले देनी चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि जो इलाके आगे बढ़ गए हैं उनकी तरफ ध्यान न दिया जाए, लेकिन जो इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं जहां पानी नहीं मिलता उनको पानी न मिले तो बड़े शर्म की बात है, हमें शर्म आनी चाहिए । मैं गवर्नमेंट की इस बात पर सराहना करता हूँ कि गवर्नमेंट ने इन पिछड़े हुए इलाको की तरफ ध्यान दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पावर प्रोजैस्ट के लिए 3356 लाख रुपया रखा है, यह काफी बड़ी अमाउंट है । इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी हमारी बिजली की मांग पूरी नहीं हो सकती, इसमें डैफिशिएंसी रहेगी यह डैफिशिएंसी 1973-74 के आखिर तक 879 मैगावाट के करीब रहेगी । इस डैफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा और कदम उठाए जाने चाहिए अगर बिजली की

डंफिशिएंसी चलती रही तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों सफर करेगे । पिछले साल हमारे यहा कहत पड़ा । आप यकीन मानिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मे, बैकवर्ड एरिया के नाते से बिजली बोर्ड ने काफी बिजली दी । पूरी बिजली तो नही दे सके लेकिन फिर भी अगर बिजली बोर्ड हमारी हैल्प न करता तो हम जिन्दा नहीं रह सकते वे, हमें कायम रखने के लिए बिजली बोर्ड ने बड़ा सहयोग दिया । इस साल भी किसी हद तक बिजली ठीक जा रही है, मैं यह नहीं कहता कि नही जा रही, जा रही है लेकिन उस पर कट है । हालांकि सी 0 एम 0 साहब ने कहा था कि कट नही एं । जब मैंने एस 0 डी 0 ओ 0 से कहा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास डिपाटेमेंट की तरफ से कोई कट नहीं है लेकिन भाखड़ा मैनेजमेंट की तरफ से इक्वूकशन्ज आ जाती हैं और हमे करना पड़ता है । इसलिए मैं सरकार से अर्ज मैं चाहता हूं कि इस सर्दी के टाईम में जहा कोल्ड वेव चल रही है इससे सरसों की फसल खराब हो जाएगी अगर बिजली पर कट लगेगी । जमीदारों ने छोटे छोटे ट्यूबवैल लगाये हु वे तबाह हो जाएगे । मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वहां पर कोई कट नही लगेगी ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जवाहर लाल नेहरू कैनल पर 30 करोड़ रुपया खर्च होने जा है वह इलाका जो पानी के लिए तरसता था, लोग सोचते थे कि हमारे खेतों में नहर आएगी पानी आएगा, खेत लहरायेगे और उनके बच्चे भी मुस्करायेगे, कपड़ा भी पहनेंगे किस्म की भावना उनके मन में थी । इसके साथ-साथ मैं

यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में स्कीम के लिए जो रुपया रखा गया वह कम है सिर्फ 36 3 लाख रुपया रखा गया है मुझे पता चला है कि शायद सैन्टर से इस के लिए हैल्प मिलेगी । मैं कहना चाहता हूं बजट में ज्यादा रुपया रखना चाहिए जैसा कि सी 0 एम 0 साहब ने वायदा था कि स्कीम को दो साल में एग्जिक्यूट कर दे-गे, तो दो साल में एग्जिक्यूट करने के लिए 36 लाख दो बजाये 10/15 करोड रुपया रखना चाहिए मैं समझता हूं कि यह नाकाफी है और ज्यादा से ज्यादा रुपया रखा जाना चाहिए । इसके इलावा रोहतक-भिवानी-रेल-लिक के लिए कुछ रुपये की डिमांड को गई है । मैं समझता हूं कि यह लिक बनना चाहिए बैकवर्ड इलाके में ब्राड-गेज लाईन ले जानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि लोहारू, भिवानी, तोशाम वगैरा इलाके ज्यादा बैकवर्ड है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी एक्सटेंशन महेन्द्रगढ तक की जानी चाहिए तभी इससे पूरा फायदा हो सकता है हर डिस्ट्रिक्ट को ब्राड-गेज लाइन कवर करती है लेकिन महेन्द्रगढ को कवर नहीं करती । जब तक यह लाईन नहीं होगी तब तक वहा इंडस्ट्री डिवेल्प नहीं कर सकती ब्राड-गेज लाइन होने से कोयले को लाने ले जाने में सहूलियत मिलती है इंडस्ट्री एस्टेवलिश करदे में सहायता मिलती है, और भी कई प्रकार की सहूलियतें मिलती है । इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको महेन्द्रगढ तक एक्सटैड किया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे प्रान्त में जे० बी ० टी० टीचर्ज बहुत हैं जो चार-चार साल से बेरोजगार फिरते हैं । एक मामूली दुकानदार अपने लड़के को जे ० बी ० टो ० करवाकर सर्विस करवाना चाहता है, थोड़े से मोल्ड का आदमी होता है, अगर उसका लडका चार चार साल तक घर बैठा रहे तो सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है । इन प्रोफैशनल स्कूलों में इस प्रकार को ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे इतने नम्बे अर्से तक ये बेरार न चे । इस विस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब जे ० बी ० टी ० कालेज से लडका बाहर आता है तो वाहर आते-आते वह एबजार्ब होता जाए । इसी तरह से इंजीनियरिंग के लडके फिरते हैं । जिन लडकी ने कुरुक्षेत्र और चण्डीगढ़ से इंजीनियरिंग पास की हुई है उन को सर्विस नहीं मिलती, बेकार फिरते हैं । इसलिए मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि एस्पैशली उन लडको को जो प्रोफैशनली ट्रेंड हैं, उनको अन-एम्पलायमेंट का, बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए, उनकी आने-जाने के लिए खर्चा दिया जाए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे नडको को भत्ता जरूर दिया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह वायदा किया गया है कि सरकारी एम्पलाईज को डीयरनेस अलाउंस देंगे । मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार को भी बपने एम्पलाईज को डीयरनेस अलाउंस देना चाहिए जबकि दूसरी स्टेटों की सरकारो ने दे दिया है खास कर उन लोगों की देना जरूरी है जो छोटे-छोटे मुलाजम है, छोटी-छोटी तन्खाह लेते हैं, जो अपने बच्चों का गुजारा नहीं

चला सकते दस-बीस मुलाजम मुझे मिले और कहने लगे -नमक के साथ खाना खाकर भी हम गुजारा नहीं कर सकते, इनको इमिजिएट डीयरनैस अलाउंस दिया जाए लेकिन बजट में इनके लिए कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया । बजट में 18 करोड़ का डैफिसिट है । अगर डीग्रनैस अलाउन्स देंगे तो डैफिसिट और बढ़ेगा 300 करोड़ का पब्लिक डैट है जो कि बहुत ज्यादा है और इसको रिड्यूस करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिएं

इसके इलावा बैकवर्ड एरियाज के लिए बैकवर्ड एरियाज में डिवैल्पमेंट करने दो लिए सरकार ने प्रायरिटी नहीं दी है । कुछ ध्यान रखा गया है, इस में शक की बात नहीं लेकिन? जो ज्यादा प्रायरिटी देनी चाहिए, वह नहीं दी गई । कल पगसों एक सप्लीमेंटरी का जवाब ककै हुए सी ० एम ० साहब ने फरमाया था कि नारनौल में सीमेंट फ़ैक्टरी जो लगा रहे थे बस नहीं लग रही क्योंकि इससे जो सीमेंट पैदा होगा वह दूसरे प्रान्तों में जाएगा इसलिए वहां मे चूना बनायेगे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो फ़ैक्टरी हम लगाते हैं और जो माल वह फ़ैक्टरी बनाती है वह बाहर भी जाना चाहिए आप देखें, हरियाणा से कितना माल बाहर जाता है? गेहूं पैदा करते है वह बाहर जाता है, और भी कई चीजें बाहर जाती है । इसी तरह से अगर यह फ़ैक्टरी लग जाती तो इससे भी माल बाहर जाता जो भी फ़ैक्टरी लगती उससे जाता । नारनौल में बहुत सीमेंट तैयार हो सकता है क्योंकि वहां लाईम-स्टोन बहुत है

। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस को दोबारा एग्जामिन कर लें और वहां सीमेंट फैक्टरी जरूर लगाई जाए, वह इलाका बड़ा बैकवर्ड है । प्वायट पंजाब में आयरन-ओर की फैक्टरी 10 करोड़ रुपये की लागत से लगाने का विचार था लेकिन वह खत्म हो गई । वहां यह प्लांट लग सकता था क्योंकि रा-मैटीरियल महेन्द्रगढ से निकलना था अगर लगा लेते तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वहां मिनरल निकालने के लिए माईन्ज है अगर फैक्टरी लग जाती तो बहुत अच्छी बात होती । वहां कौपर की माइन्ज हैं, इसको एक्सप्लोरेट करना चाहिए और इससे हरियाणा के रिसोर्सिज बढ़ सकते हैं

डिप्टी स्पीकर साहिबा, रोडज पर बड़ी चर्चा हुई और सरकार ने कहा कि हम रोडज पर इतना ध्यान नहीं देंगे । लेकिन दो तीन रोडज ऐसी हैं जिनका बनाया जाना निहायत जरूरी है । गाव की पंचायतों ने पांच-पांच, दस-दस हजार रुपया कंट्रीब्यूट किया है और जमा किए हुए पांच-पांच साल हो गए है लेकिन नहीं बनीं जो सड़कें बननी हैं उन के नाम हैं-कनीना टू ककराला और गुधा टू रसालपुर । तो मेरा निवेदन है कि जिन पंचायतों ने दस हजार का या पांच हजार का कंट्रिब्यूशन दिया है उनकी सड़कें जरूर बननी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, वाटर सप्लाई के ऊपर 176 लाख रुपये सरकार खर्च करने जा रही है । मैं यह कहूंगा कि यह रकम बहुत मामूली है । डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ का सारा डिस्ट्रिक्ट

ऐसा है जहां पीने का पानी अच्छा नहीं है । बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां मीठा पानी है । वहां या तो बारिश का पानी लोग पीते हैं या फिर उन जोहड़ों को लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका पानी हैवान भी नहीं पी सकते । तो ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए जो सारे महेन्द्रगढ़ को पानी सके

डिप्टी स्पीकर साहिबा, वहां एक दोहान नदी है । उसने पीछे आस-पास के इलाके को बड़ा नुकसान किया जो अच्छे खेत थे उनको स्वायल इरोजन से या तो काट दिया या उनमें रेत ही रेत डाल दिया । तो उससे आस-पास के खेतों और महेन्द्रगढ़ शहर को बड़ा खतरा इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां तक छोटे डैम को शकल में या दीदार की शकल में कोई ऐसी चीज बनाएं जिससे इस खतरे को टाला जा सके.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहेगा इस प्रान्त में काफी काम हुआ इसमें कोई दो राय की बात नहीं है लेकिन साथ-साथ कुर्रप्शन भी कुछ बढ़ती गई है इस कुर्रप्शन को दूर करने के लिए भी सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए । आज और बातों के अलावा गवर्नमेंट सर्वैन्ट्स जीपस का मिसयूज भी बहुत करते हैं. आज चूंकि पेट्रोल की कमी भी है और मंहगाई भी है इसलिए हमें इस मिसयूज को भी रोकना चाहिए ।

जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके द्वारा जब तक करैक्टर की भावना हम बच्चों के अन्दर पैदा नहीं कर सकेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम ज्यादा डिप्लमैंट नहीं कर सकेंगे । किसी प्रान्त या नेशन की ग्रेटनेस उसके नैचुरल रिसोर्सिज से ही होती या दूसरे कारणों से नहीं होती बल्कि उसके अच्छे सिटिजन्ज से होती है । जिस देश या प्रान्त में महान सिटिजन्ज रहते हैं वही देश या प्रान्त महान होता है । तो हमें चाहिए कि हम शिक्षा के द्वारा ऐसे विद्वान सिटिजन्ज पैदा करें जो महान हों, करैक्टर के आदमी हों और आगे चल कर बड़ी हिम्मत ओर ईमानदारी के साथ डिप्लमैंट का काम करें । इन शब्दों के साथ,

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सदन में तीन रोज से बजट पर डिसकशन चल रही है । गवर्नर साहब का जो अभिभाषण है उस पर बोलते हुए मैंने हरियाणा ने जो फिनौमिनल तरक्की की है इन आल रिसपैक्टस उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाया था । मेरे काबिल दोस्त श्री दौलता साहिब जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मुझे मुबारिकबाद दी । पहली बात, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं उनसे मुबारिकबाद लेना नहीं चाहता कारण कि गलत आदमी की मुबारिकबाद कभी अच्छी नहीं होती । ये

दोस्त ये चाहेगे कि एरसे शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ । मैं उनका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ । शायद उन्हें हमारे मुख्य मंत्री साहब से कोई पर्सनल शिकायत हो । मैंने जिस वक्त हरियाणा की तरक्की की तसवीर खेची थी उसके तीन फ़ैक्टर्ज मैंने अर्ज किए थे डिप्टी स्पीकर साहिबा, अक्वल यह कि हरियाणा में तरक्की इसलिए हुई कि हरियाणा बना, दूसरा यह कि तरक्की इसलिए हुई कि आज सरकार कांग्रेस पार्टी के हाथ में है जिसका प्रोग्राम प्रोग्रैसिव सोशलिज्म लाने का हूँ और गरीबों की भलाई का है । तीसरा मोस्ट इम्पोर्टैन्ट फ़ैक्टर जो है वह यह है कि उस प्रोग्राम की पालिसी की ऐक्विक्वूशन आज चौधरी बंसी लाल कर रहे है अगर बंसी लाल जी न होते तो यह तरक्की न होती । क्यों? हरियाणा बनने कर बाद मेरे दोलत भी सरकार मे रहे लेकिन तरक्की नहीं हुई बल्कि हरियाणा का नाम बदनाम हुआ फिर हरियाणा बनने के बाद कुछ दिनों तक हरियाणा सरकार की बागडोर ऐसे शक्स के हाथ में रही जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिटर थे लेकिन उस समय भी तरक्की नहीं हुई । इसलिए सिर्फ हरियाणा बनने से या सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हकूमत होने से तरक्की नहीं होती बल्कि जब तक ऐक्विक्वूटर अच्छा न हो, ऐडमिनिस्ट्रैटर अध्यक्ष न हो उस वक्त तक तरक्की नहीं होती डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको तो मालूम ही कि जैनीज्म मे सालवेशन के लिए तीन फ़ैक्टर्ज जरूरी है । नम्बर एक, राईट नालेज, नम्बर दो। राईट थीकिंग और नम्बर तीन जो कि मोस्ट इम्पोर्टैन्ट है वह तुँ राईट ऐक्शन । ऐक्शन के बगैर सालवेशन

नही होती इसलिए जब तक ऐक्शन करने वाला आदमी प्रौपर न हो तरक्की नहीं होगी मैं एक बात और अर्ज करूंगा दौलता साहब, एक अच्छे वकील समझे जाते हैं लेकिन कोई भी वकील अच्छा नहीं समझा जाता यदि वह एट दी बार किसी विटनैस की एवीडेंस को या किसी रूलिंग को गलत कोट करे । मैंने तीन बातें दही थी । अगर इन तीनों बातों के बारे में ये कुछ कहते तो मैं उसका अन्दर करता लेकिन' अगर चीफ मिनिस्टर साहब से उनकी कोई जाती शिकायत हो उसमें मुझे ये कोट न करे, मुझे आयंदा बीच में न लाएं, यह मेरी इनसे मुअदबाना गुजारिश है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इनकी तीनों बातों से ऐग्री करता हूं ।

श्री गुलाब सिंह जैन : थैकयू । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बजट पर मजीद बोलने से पहले अपने मुख्य मंत्री जी का तमाम ट्रेडिंग कम्यूनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कारण कि पिछली दफा जब हाउस में सेल्ज टैक्स से बारे में बिल आया तो मैंने कुछ आपत्तियां उठाई थी और मेरे मुख्य मंत्री जी ने अश्योरेंस दी थी कि ऐसी बातें जिनके बारे में ट्रेडिंग कम्यूनिटी समझती है कि वह उनके साथ ज्यादाती है उनको सरकार दूर करेगी । कल हाउस में एक अमैंडिंग बिल डिस्ट्रिब्यूट हुआ और उसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे खुशी हुई कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो अश्योरेंस यहां हाउस में दी थी या हाउस के बाहर जब व्यापारी उनसे मिले और अपनी मुश्किलात उनके सामने रखी और इन्होंने

फराखदिली से वायदा किया था आज उस वायदे को पूरा करते हुए सरकार अमैडिंग बिल हाउस के सामने लाई है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं उनका मश्कूर हूं । इसके बाद मैं अपने वित्त मंत्री साहब काभी मश्कूर हूं क्योंकि उन्होंने हिसार की डिवैल्पमेंट को तरफ खास तवज्जुह दी है । हिसार ओवर ब्रिज का गवर्नर अभिभाषण में और तक स्पीच दोनों में जिक्र है । वाक्या ही इसकी वहा बड़ी जरूरत थी. हिसार की डिवैल्पमेंट बगैर नामुक्कमल थी. इसी तरह से जुडीशियल कंप्लैक्स, जिसका उदघाटन अभी गर्वनर महोदय करके आए हैं, भी देखने के लायक चीज है । अगर मैं कहूं कि सारे हिन्दुस्तान में मूकाबले काजुडीशियल कंप्लैक्स नहीं है ते शायद गलती पर ने हूं ' मुझे अपने प्रोफैशन वजह से तमाम हिन्दुस्तान में घूमने का मौका मिलता है लेकिन मैंने उस तरह का वैल— डिवाइन्ड, वैल प्लान्ड और वैल कंस्ट्रक्टिड जयूडीशियल कंप्लैक्स कही नहीं देखा तो उसके लिए भी मैं सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं । हिसार के लिए वजट स्पीच में डिप्टी साहिबा, एक और चीज का जिक्र भी है और वह यह है कि हिसारके अन्दर रिक्रिएशन के लिए चक्रवर्ती की तरह की एक लेक बनाई जाएगी । इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं और का मैं मश्कूर हूं । वहां ये मिल्क प्लाट भी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं सरकार का मश्कूर हूं ।

इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चन्द बातें जो बड़ी जरूरी हैं कहना चाहूंगा । तो यह है कि बजट के ऊपर डिसक्रेशन करते हुए मेरे दोस्त श्री राम लाल जी ने, जो जनसंघ का मैम्बर हैं, एक बात कही । जब वे बात कह रहे थे, उससे पहले मैं उनकी इज्जत करता या लेकिन उस बात के कहने के बाद मैं सोचने लगा कि या तो वे बजट को समझ नहीं रहे हैं या फिर वे मिस-स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स कर रहे हैं जो कि जनसंघ वालों की आदत है । दोनो में से कोन सी बात दुरुस्त है यह मुझे पता नहीं । (विधन)

Please do not disturb me. When you speak, I do not disturb.

Deputy Speaker : No Interruptions please.

श्री गुलाब सिंह जैन : तो मैंने एक अर्ज करनी है । उन्होंने कहा कि किसी बजट को देखते हुए हमें देखना पड़ता है कि उसका रैवैन्यू कितना है और उस रैवैन्यू की कुलैक्शन और रियालाइशन में परसेंटज आफ एकसपेडींचर क्या हैं क्योंकि बजट का एक का सूत्र है कि सरकार अगर ऐसा टैक्स लगाए जिसकी कुलैक्शन में बहुत ज्यादा खर्च आए वह टैक्स लगाया नहीं जाना चाहिए । यह एक असूल है और इस असूल को हमको देखना पड़ता है । एक साहब ने एक दो परटीकुलर आइटम्ज का जिक्र करके यहां कहा कि कुलैक्शन पर पचास परसेन्ट खर्चा होता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपके द्वारा सदन में आकडे रखना

चाहता हूँ हमारा जो टोटल बजट है उसके तीन हिस्से होते हैं । पहला हिस्सा होता है टैक्स रैवेन्यू, दूसरा हिस्सा होता है नान टैक्स रैवेन्यू और तीसरा होता है ग्रान्ट इनऐड । जो खर्चा रियलाइजेशन का होता है, टैक्स रैवेन्यू होता है । ग्रान्ट इन ऐड और नाल-टैक्स रैवेन्यू पर नहीं होता । हमारा टैक्स लाख 90 करोड़ और 56 लाख हैं । इसमें से अगर हम वह आइटम जो 9 करोड़ और 46 रैवेन्यू 90 रुपये की है, वह घटा दे, जो कि हमे सैन्टर से आता है और जिसकी रियलाइजेशन हरियाणा सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता तो हमारा कुलैक्शन पर केवल दो करोड़ और 78 लाख रुपया रह जाता है यह 35 परसेन्ट बनता है

डिप्टी स्पीकर साहिबा जो हमारे अपने एक्साइज एन्ड टैक्सेशन मिनिस्टर हैं उनको मुबारिकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा का टैक्स रैवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और सेल्ज टैक्स से आता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मैं यह अर्ज करूँ कि एक्सपाइज ड्यूटी को कुलैक्शन का एक्सपैडीचर इतना कम है जो कहीं भी नहीं है तो गलत नहीं होगा । मैं खुद उसकी परसेन्टेज निकाली है । मैं तो देख कर हैरान हुआ कि 15 करोड़ 50 लाख रुपया आता है और जो खर्चा होता है वह उस पर 2 लाख 72 हजार रुपए है । यह खर्चा 0.8 परसेन्ट बनता है यानी एक परसेन्ट से भी कम है डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने दूसरी स्टेट के बजट भी देखे हैं और मुझे सैन्टर गर्वनमैट का बजट

स्टडी करने का भी मौका मिला है इतने लो एक्सपैसीज, इतने कम रियलाइजेशन एक्सपैशनसीज आज तक कही भी हिन्दुस्तान की किसी स्टेट में नहीं हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे सेट्ज टैक्स का जा कुलैक्शन एक्सपैक्ट करते हैं वह 32 करोड़ है और उसके अगेन्सट में जो उसकी कुलैक्शन पर एक्सपैशनसीज है वे केवल 65 लाख है । कितने कम हैं यानी दो परसेन्ट है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कहना कि हरियाणा के अन्दर जो टैक्स लगाये जा रहें है वे बहुत ज्यादा हैं और उनकी कुलैक्शन पर जो खर्च किया जा रहा है वह बहुत ज्यादा है । यह गलत है । दरअसल क्या वजह है? जिन्होंने यहां पर लैन्ड रैवेन्यू का जो जिक्र किया है उनका अगर इस बात का नालेज नहीं है तो मैं आपके जरिए उन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि लैन्ड रेविन्यु का जो खर्चा है वह कुलैक्शन का खर्चा नहीं है, दरअसल लैन्ड रैवेन्यू डिपार्टमेंट मल्टीफीरियस काम करता है । उसका जो मैन फंक्शन है वह लैन्ड रैवेन्यू रिकार्ड ठीक रखने के लिए होता है । उसका काम कोई टैक्स वसूल करना नहीं है । उसका काम तो कुरैक्ट लैन्ड रिकार्ड मेनटेन करना है । वह जो भी खर्चा है वह कोई टैक्स कुलैक्शन का नहीं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह बात अर्ज करना चाहता हूं जो कि यहां हाउस में बोलते हुए, मेरे एक माननीय सदस्य चौधरी चान्द राम जी ने कही । मुझे उनकी जात से कोई शिकायत । नहीं, कभी मेरा उनके साथ ज्यादा वास्ता नहीं रहा ।

कुछ असूल की बातें उन्होंने कहीं और, असूलन ही मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को हरिजन स्पोर्ट न करे तो रह ही क्या जाता है । मैं यह कहता हूँ कि अगर हरिजनों को कांग्रेस स्पोर्ट न करे तो हरिजनो के पास है क्या? आज हरिजनों की जो पोजीशन है वह कांग्रेस की वजह से ही है । सर्दियों से ये लोग दबे हुए थे । ब्राह्मणो ने इनको उठने नहीं दिया । आज भी अगर वे उन्हें नहीं उठाने दें तो फिर उनकी क्या हालत हो? अगर उनके लिए महात्मा गांधी जी ने आवाज नहीं उठाया होती और कांग्रेस पार्टी ने आवाज न उठायी होती तो मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूँ जो । मेरे दोस्त उधर बैठे हुए हैं, जो बढ़-चढ़ कर हरियाणा की बहबूदी की बातें करते हैं, उन्हें चौलेन्ज करता हूँ वे कुछ नहीं कर सकते थे । सब से पहले हिन्दुस्तान में आज के युग से जिस शख्स ने हरिजनों के हक में जबान खोलने का साहस किया था वह कोई हरिजन नहीं था, वह स्वामी दयानन्द था जो कि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था । उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने रुब्लणिज्य के खिलाफ आवाज उठायी थी । डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको भी पता है इसी तरह से लार्ड महाबीर ने आवाज उठायी थी, लार्ड बुद्धा ने आवाज उठायी थी और आचार्य शकराचार्य ने उनको हिन्दुस्तान से बाहर फेका । सिर्फ जैनिज्म हिन्दुस्तान में रहा वह भी ब्राह्मणिज्म का लवादा ओढ़ कर रहा । मुझे यह कहने में ताम्मुल नहीं कि अगर कोई दूमरी शख्सीयत थी जिन्होंने हरिजनों के लिए अपनी जान को बाजी लगायी वे थे महात्मा गान्धी । अगर कोई पार्टी है जो

हरिजनों की भलाई चाहती है वह केवल कांग्रेस पार्टी ही है । मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि उनके वे दिन न रहें अगर हिन्दुस्तान में कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का राज हो । मैं अपने काबिल दोस्त से यह पूछना चाहता हूँ कि वे किस पार्टी का राज चाहते हैं । क्या वे कांग्रेस के अलावा जनसंघ का राज चाहते हैं । अगर कांग्रेस पार्टी का राज न रहे, क्योंकि डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट बदलती रहती है । क्या वे मेरे दोस्त जनसंघ का राज चाहते हैं जिसको मैं ब्राह्मण पार्टी मानता हूँ । मेरे एक दोस्त हैं जो कलकत्ता में वकील है । वे बड़े जनसंघी हैं । मैंने उनसे पूछा कि बम्बई स्टेट में जहां पूना में जनसंघ का हैडक्वार्टर है, जहां पर दस हजार ट्रेन्ड वरकरज हैं और कलेम करते हैं कि हमारी बड़ी ताकत है फिर भी आप वहां इलैक्शन में हार जाते हैं उसका क्या कारण है? उन्होंने बड़ा ईमानदाराना जवाब दिया कि हम इसलिए हारते हैं कि वहां पर हमें एक ब्राह्मण पार्टी समझा जाता है और जो नान-ब्राह्मण है वे हमें वोट नहीं देते हैं । अगर इसके बाद ऐसा हो कि देश में कभी इस पार्टी की हकूमत बने, तो मैं अपने दोस्त को बतला देना चाहता हूँ कि उनका इस हकूमत में हरिजनों के साथ इतना गलत ट्रीटमेंट होगा जिसके बारे में ब्यान नहीं जा सकता है । जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, क्या वे राइटिस्ट पार्टी उनका भला कर सकेगी? क्या बी० के० डी० पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी उनकी मदद कर सकती हैं और दूसरी आल इंडिया पार्टी है कम्युनिस्ट । क्या आप उनका राज चाहते हैं । वे यह कहने की साफ तौर पर हिम्मत करें । डिप्टी स्पीकर साहिबा,

जो भाई दूसरे देशों से हो कर आये हैं उन्होंने डैमोक्रेटिक वे आफ लाइफ को देखा कब और टोटेलीटेरियन सिस्टम आफ गवर्नमेंट का भी अनुभव होगा । हमारे यहां तो वे आफ लाइफ डैमोक्रेटिक सिस्टम आफ गवर्नमेंट है । कांग्रेस पार्टी से कोई और बढ़िया पार्टी हो नहीं सकती है । हरिजनों का जितना कांग्रेस पार्टी ख्याल रखती है उतना कोई ख्याल मार्ग रखता है । जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री साहब ने हाउस में बोलते हुए कहा था कि श्रीमती इंदिरा गान्धी से ज्यादा और कोई भी हरिजनों का इतना भला चाहने वाला नहीं हो सकता । मैं यह कहने में तामुल नहीं करता कि हरियाणा के मुख्य मंत्री जी का हरिजनों की तरफ गरीबों की तरफ जितना ध्यान है और किसी का हो नहीं सकता । हरियाणा सरकार की जब वे से चौधरी बंसी लाल के हाथ में बागडोर आयी है तब से उन्होंने हरिजनों को काफी ऊंचा उठाया है । अगर यह कहा जाये कि जो कदम उठाये हैं वे थोड़े हैं तो मैं मान सकता हूँ । कोन-कौन सी ऐसी जातियां है जिनको कितनी ही सदियों से हजारों सालों से ऊपर नहीं उठने दिया गया, वे अपने हको से वंचित रहे । ऐसी जातियों को ऊपर उठाने में समय लगता है उनके लिए जितना भी किया जाये थोड़ा है । मुझे कोई इतराज नहीं है लेकिन यह कहना कि चीफ मिनिस्टर साहब का इधर ख्याल ही नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, किसी भी जाति को उठाने के लिए सब से पहले उसकी तालीम की तरफ ध्यान रखा जाता है । वह बहुत जरूरी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आयी है तब से तालीम का खास ख्याल रखा गज है । सैज़ल गवर्नमेंट ने होस्टल में दाखिल होने वाले हरिजनों के लिए स्कालरशिप रखा, लेकिन हमारी सरकार ने उसको कम समझा । हमारी सरकार ने 15 रुपये महीना देना शुरू कर दिया । जहां तक फीस माफी का सम्बन्ध है वह भी सर्भा हरिजनों को लाभ हो चा है । आज हमारे हरिजन भाई वी ० ए ० और एम ० ए ० कर चे हैं । जब मै पड़ता था तो मेरी क्लास में केवल एक हरिजन लड़का होता था । कोई भी उसके साथ नहीं बैठता था एक बेच हाता था योर उस पर दो सीटें होती थी । मुझे गर्व है कि वह मेरे साथ ही बैठता था, वह मेरे बैन्च पर बैठा करता था क्योंकि वह भी गरीब था और मैं भी गरीब था । जो आज गुलाब सिंह है यह उस वक्त नहीं था जो आज है । शायद उन लोगों ने जिन्दगी में गरीबी देखी हो लेकिन मैंने गरीबी को चखा है । मुझे पता है कि गुरबत क्या होती है, मुझे पता कि गुरबत में क्या तकलीफ होती है । मेरी उन दोस्तों के साथ पूरी सहानुभूति है जो गरीब की भलाई की बातें करते हैं और हरिजनों को भलाई की बातें करते हैं । मुझे उनसे पूरी पूरी सहानुभूति है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर भंहगाई के बारे में भी जिक्र किया । मैं मानता हूं कि देश में भंहगाई है । (व्यवधान)

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, गुलाब सिंह जी किसी की स्पीच में इन्ट्रूट नहीं करते हैं इसलिए इनकी स्पीच में यदि कोई इस्ट्रूट करे तो इन्हें और टाईम मिलना चाहिये । ये जनसंघ वाले साथी इनको इन्ट्रूट करते रहते हैं ।

Deputy Speaker : Order please. No interruptions. Please take your seat.

श्री गुलाब सिंह जैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था कि यहां पर मंत्री का जिक्र किया गया । मैं मानता हूं कि देश में मंहगाई है और मंहगाई को हटाया जाना भी बहुत जरूरी है । हम प्रोडक्शन के आंकड़े देखें कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस वक्त देश में प्रोडक्शन की पोजीशन क्या थी और आज प्रोडक्शन की क्या पोजीशन है । अगर मैं वह आबाड़े बतलाने लगू तो उनसे यह नज़्र आयेगा कि देश में बहुत तरक्की हुई है इस तरक्की के दौरान जहां हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है वही उसके साथ-साथ इनफ़्रा-स्ट्रक्चर को भी रंदा किया है । हमारे देश की पापुलेशन बढ़ती जा रही है । हमने फ़ैमिली प्लानिंग की तरफ भी ध्यान दिया । मुझे कह दाहने में के।इ।हिचकिचाहट नहीं है कि परसुएशन से फ़ैमिली प्लानिंग होने वाली नहीं है । जो सोशल रिफ़ार्मर होते हैं वे किसी देश में किसी गवर्नमेंट के हाथे मजबूत करने के लिये एक माहौल पैदा करते हैं ताकि सरकार स्ट्रॉन्ग ऐक्शन ले सके । फ़ैमिली प्लानिंग के प्रोपेगन्डे के जरिये आज यह माहौल है कि हर आदमी इस बात

को समझता है कि फैमिलीप्लानिंग होनी चाहिये । मेरा इस बारे में यह सुझाव है कि इसे कानूनन लागू करना चाहिये । जब तक फैमिली-प्लानिंग को कानूनन लागू नहीं करेंगे या इसके रियि कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक यह पापुलेशन की जो ऐक्सप्लोजन है, वह रुकने वाली नहीं है । अगर पापुत्रे छान कर ऐक्सप्लोजन नहीं रुकती हैं तो हम चाहे कितने भी प्रोडक्शन बढ़ाते जायें उसका कोई फायदा नहीं होगा । हमारी प्रोडक्शन अगर उस प्रोपोरशन से नहीं बढ़ती है जिस प्रोपोरशन से पापुलेशन बढ़ती जा रही है तो मंहगाई बढ़ती जायेगी, इसलिये इस ओर खास ध्यान दिया -गाना चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक और प्लैलीकेट सच्चौकट टच करना चाहना हूं । जो आज देश में आर्थिक संकट नजर आता है उसकी वजह स्ट्राईक भी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह मानता हूं कि लेबर का स्ट्राईक करने का राईट है । मैं उनको इस राईट से वंचित नहीं करना चाहता । लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि जिस वक्त ये ट्रेड-यूनियनें वनी और लेबर को स्ट्राईक का हक दिया गया उस वक्त उसके पीछे रीजन क्या ढग था । As against capitalists, unorganised labour is weak. उस वक्त यह रीजन था कि जिस कैपिटलिस्ट की ऐक्सप्रायटेशन से लेबर को बचाने के लिये लेबर जो हो, वह आर्गेनाइज्ड हो मैं इस प्रिंसीपल को मानता हूं । लेकिन आज इस देश जै अन्दर हालात क्या है? हालांकि कांग्रेस पार्टी की अन्मनी पालिसी लेबर के फेवर में है

कांग्रेस पार्टी आज देश से गरीबी को दूर करना चाहती लूँ सोशलिस्टिक पं टर्न लाना चावृती है, क्लासलैस सोसाइटी क्रिकेट करना दाहती है तो क्या वजह है आज स्ट्राईकस करायी जा रही हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जप जानते हैं कि लेबर के फायदे की जो बात है, वह गवर्नमेंट खुद सोचती है । डिप्टी सीकर साहिबा, सारे देश की जो पापुलेशन है वह लरज 550 मिलियन है और इसका 80 प्रति- शत हिस्सा देहात में रहता है । आपको पता है कि देहाती स्ट्राईक कग्रता नहीं है, हमारी जो फार्म लेबर है, वह भी स्ट्राईक नहीं करती । आज हमारे यहां जो गवन मैट में, चाहे पब्लिक सैक्टर में हों या प्राइवेट सैक्टर में हो, कुल मिलाकर जो ऐम्पलाईज हैं, वे 18 मिलियन हैं इन 18 मिलियन ऐम्पलाईज के दायरे के अम्बर ही ये सारी गड़बड़ होती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सीमेंट की कमी होती है । किस लिये? इसलिये या तो सीमेंट की फैक्ट्रीज मे स्ट्राईक की वक्ह से प्रोडक्शन कम होती है या फिर रेलवे में स्ट्राईक होने की वजह से माल पहुचता नहीं हैं । आज वैजीटेबल भी की भी यही पोजीशन बनती जा रही है दुःख उस वक्त है जब हमारी मेजर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज के अन्दर स्ट्राईक होती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपको 1971 के आकड़े बताना चाहता है कि कितना ग्रौस नैशनल लास हुआ है रन अन-नेरुंसरी स्ट्राईकस की वजह से । हमारे 12,07,50, 244 वर्किन्ग डेज वेस्ट हुए हैं अगर इन वर्किन्ग डेज को प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाये तो यह पता चलेगा कि कितना बडा प्रोडक्शन सं लास हुआ है । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं

कि इससे देश को क्तिना नुकसान उठाना पड़ रहा है । आज जब देश में रेलवे में या किसी दूसरी जगह स्ट्राईक होती है मे उससे जो डेज लास होते हैं, उसका इफैक्ट ओवर-अम्ल हमारी प्रोडक्शन पर पडता है । से लोगों तक कोल नहीं पहुंचता । फ़ैक्ट्रीज तक नेसैसरी रा-मैटीरियल नहीं पहुंचता जिसकी वजह ले लोगों तक फिनीशड गुड्ज नहीं पहुंचती । इसका इस प्रकार से दो तरफा नुकसान है । मैं आपके द्वारा यह अर्ज करूंगा कि हरियाणा सरकार को इसके बारे में कोई रास्ता दिखाना चाहिए । मैं मजदूर के खिलाफ नहीं हूं । मैं सरकारी मुलाजिम के भी खिलाफ नहीं हूं । मेरी यह क्न्यीक्शन है डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज जो स्ट्राईक्स होती हैं, इनकी बैंक मे कुछ और ही चीज है । वह मजदूर की भलाई को बात नहीं है । मैं स्ट्राईक्स और लाक-आउटस दोनों के ही खिलाफ हूं। खाली स्ट्राईक के ही नही, वाक-आउट के भी खिलाफ हूं । हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसके द्वारा हम स्ट्राईक्स को आगे के लिये बन्द कर सके । मैं चाहता हूं कि कम से कम हम उन लोगों को परसुऐशन से स्ट्राईक्स से हटायें जो स्ट्राइक्स की तरफ जाते है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक चीज मैं और अर्ज करना चाहता हूं । हमारे, यहां हिन्दुस्तान में तीन-चार बड़ी ट्रेड यूनियनें हैं, वे हैं इंडियन- नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस । इनकी अपनी ही इन्टरनल पौलिटिक्स की वजह से कितनी ही जगहों पर स्ट्राईक्स होती है और उसका रिजल्ट यह होता है कि देश का नुकसान

होता हूँ । वे नैशनल इट्रैस्ट में नहीं की जाती, वे मजदूर के इट्रैस्ट में भी नहीं होती, जो स्ट्राईक्स होती हैं, उनके पीछे मुद्दा कुछ और ही होता है । इसलिये इस के बारे में हमें कुछ इफैक्टिव स्टैप्स लेने पड़ेंगे । जो मजदूर की जायज मांग है, जो मजदूरों की बेहतरी की बात है, जो मुलाजिमों की बेहतरी की बात है, उसको सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिये । कल कुछ भाई मेरे से मिलने आये थे । अगर हम लैजिस्लेटज उनकी जायज तकलीफ को दूर नहीं करते हैं तो हमें ऐग्जिस करने का कोई राईट नहीं है, हमें स्टैंड करने का कोई राईट नहीं है । We should be of use to all right persons to vindicate their right purposes. डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर सरकारी मुलाजिमों की बात कही गयी ।

उपाध्यक्षा: गुलाब सिंह जी, आप जरा जल्दी वाईन्ड अश्व करने की कोशिश करें ।

श्री गुलाब सिंह जैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने मुझे आधे घंटे का टाईम दिया है, मैं आधे घंटेसे ज्यादा नहीं लूंगा । मैं सरकारी मुलाजिमों के बारे में कह रहा था । मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सरकारी मुलाजिमों को तकलीफों को बहुत अच्छी तरह से समझती है । इस महंगाई के जमाने में उनकी जो तकलीफें हैं, वे सरकार सब समझती there are hardest hit अर्थ-शास्त्र का एक प्रिन्सिपल है और वह यह है कि जब कीमतें ऊंची होती हैं तो जो फिक्सड इन्कम ग्रुप है, उनको सबसे ज्यादा

तकलीफ होती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप इन-टर्मज आफ करेन्सी उनकी चाहे कितनी भी बढ़ाते म्बे, उनके मसले का हल नहीं निकलेगा. मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपने अगर सरकारी मुलाजिमों को खुशहाल करना है, उन्हें खुश रखना है तो आप इन-टर्मज आफ कमोडिटीज उनकी पे का कोई हिसाब बनायें । ऐसा करना एक बड़ी अच्छी बात होगी । डिप्टी स्पीशर साहिबा, मैं. एक बात इलैक्ट्रिसिटी के बारे में भी कहना चाहता हूं । हमारे यहां जो इलैक्ट्रिसिटी की कन्जम्पशन का अनुमान लगाया गया है उसका बजट में. जिक्र है और वह 450 मेगावाट का है । अब तक हम जो जराये पैदा कर पाये हैं और जिनका इस बजट में भी जिक्र किया गया है, उनके मुताबिक हमारे जो प्रैजेंट रिसोर्सिज हैं वे 232 मैगावाट के हैं ओर उन के अलावा फरीदाबाद, पानीपत और वैस्टर्न जमुला कैनल से जो हम विजली पैदा करने जा रहे है इस. सब को मिला कर टोटल 617 मैगावाट बनती हैं । मैं सरकार को आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं कि आम तौर पर बिजली की खपत का जो अनमान लगाया जाता है, उसके मुकाबले में बिजली की डिमान्ड बहुत तेजी से बढ़ती है । आप जानते हैं हरियाणा के अन्दर ला एण्ड आर्डर बहुत बढ़िया है । आज हरियाणा सरकार का तमाम देश के अन्दर यह इमेज है कि यहा पर ला एण्ड आर्डर बहुत ही बढ़िया है । इसलिये हरेक इंडस्ट्रियलिस्ट हरियाणा में आकर इंडस्ट्री लगाना चाहता है । इंडस्ट्री लगाने के लिये इलैक्ट्रिसिटी का होना सबसे पहली चीज

है जिसकी उसे जरूरत पड़ती है । इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 617 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध करने का अन्दाजा लगाया है, उसको किसी न किसी तरीके से बढ़ा कर एक हजार मेगावाट तक ले जाने के लिये प्रोविजन प्रोवाइड करें तब ही हरियाणा पहले हिन्दुस्तान का और फिर दुनिया का एक अहमतरीन प्रदेश बन सकता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, तालीम के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ वै से तो जो तालीम के बारे में रजोल्यूशन चल रहा है उस पर बोलने का जब मौका मिलेगा तो मैं डिप्टेल में बोलूंगा, इस वक्त एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तालीम की क्वालिटी बढ़नी चाहिए । सरकार ने यह ठीक कदम उठाया है जो उसने अपग्रेडिंग अउफ स्कूल बंद किया है और ज्यादा नए स्कूल खोलना बंद किया हूँ । तालीम के फील्ड में जो कुछ काम किया गया है उसी को सालिड करना है । तालीम के बारे में आगे जो कुछ सरकार करे वह सिर्फ इतना करे कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर और यह करना बहुत जरूरी है । अब मैं चन्द बातें अपनी कांस्टीचूएसी वो बारेमें कहना चाहता हूँ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इरीगेशन के बारे में हमारी सरकार का खास ध्यान वै । हरियाणा एक कृषि प्रधान देश हे इसमें कोई दो राय नही हो सकती । सरकार ने लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनाकर वह काम किया है ऐसी जगह पर पानी पहुंचाया है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था । पांच-पांच सौ फुट ऊंचा पानी पहुंचाया है, यह सरकार का बड़ा सराहनीय काम है । मेरे हल्के में तीन ऐसे इलाके हैं जहां लिफ्ट

इरीगेशन के बगैर पानी नहीं पहुंच सकता । काफी एरिया हिसार प्रापर, जुगलान और एक गांव हैं शाहपुर । मेरी गुजारिश है कि इन इलाकों के अन्दर पानी पहुंचाने के लिए छोटी-छोटी इरीगेशन स्कीमें चालू की जाए । इसके अलावा पीने के पानी का जिक्र आया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे हल्के में खासतौर पर दो गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है और 1974-75 के साल में मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि एक गांव तलवंडी राना है और दूसरा गांव गंगूआ है वहां पर जटर वर्क्स लगाया जाए और लोगों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम किया जाए । कुछ नहरों पर पुलों और ब्रिज बनाने का जिक्र आया है । मैं इसके बारे में भी अर्ज करना चाहता हूँ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती होगी कि हिसार का पशुओं का मेला हिन्दुस्तान भर में मशहूर है । जहां यह मेला लगता है उस जगह का नाम सात रोड खूद है । यह जगह वैस्टने जमुना कैनल की तरफ आती है । जो लोग अपने डंगरों को लेकर आते हैं वे वैस्टर्न जमुना नहर को पार करते आते हैं क्योंकि अगर वे लोग नहर में से पशु गुजारते लाएं तो वह जगह जहां मेला लगता है, नजदीक पड़ती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर एक पुल जरूर बनाया जाए । इसके अलावा कुछ और जगह जैसे बरवाला मेन कैनल है वहां अगर बड़े पुल न बनाए जाएं तो बहा पर घोड़ा रुलिया जरूर बनाई जाएं । टूरिज्म की बाबत मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिसार के अन्दर एक डीयर पार्क है उरुको एक्सटेंड किसी जाए किसी जमाने में यह जगह लखाडार के नाम से मशहूर थी । राहा

जाता है कि वह बहुत हिरन रहते थे और जब वे गुजरते थे ले रास्ता बन्द हो जाता था क्योंकि हिरनों की बाबत कहा जाता है कि एक हिरन जिधर को चल देता है उसी तरफ को सारे हिरन चल देते हैं । आजकल तो वहां हिरन नहीं है लेकिन वह जगह उनके नाम से मशहूर है । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस डीबर पार्क को एक्सटैंड किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ ।

श्री फतेह सिंह (जुलाना) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया ।

श्री अमर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या वित्त मंत्री महोदय के बोलने से पहले मुझे टाइम मिलेगा या नहीं?

Deputy Speaker : This is no point of order. I will see and if there is time you will be given time to speak.

श्री अमर सिंह : आश्वासन तो दे दे ।

उपाध्यक्षा : मैं आश्वासन अभी कैसे दे सकती हूँ ।

श्री फतेह सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1974-75 के बजट पर बहस हो रही है इसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ । वैसे तो मेरे साथियों एं इसके बारे में बहुत कुछ रोशनी डाल दी है लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों को ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । हमारी गवर्नमेंट ने जो यह बजट बनाया

है यह बड़ा ही सराहने योग्य है । हमारे फाईनेस डिपार्टमेंट ने हर पहलू पर गौर करके, विचार करके, हरियाणा के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा मेहनत के साथ यह बजट तैयार किया है । इसकी जितनी भी ज्यादा तारीफ की जाए वह थोड़ी है । हमारे बिरोधी भाईयों ने कुछ बातें नुक्ताचीनी कैं लिए कही उनके मुताल्लिक खासतौर से जिला जींद के बारे में चौधरी धज्जा राम ने चौधरी दल सिंह की बाबत बता दी हैं । मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा. कि चौधरी दल सिंह को तीन महीने के लिए गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहने का मौका मिला था । उस वक्त ' इन्होंने न हरियाणा के लिए औरर न ही जिला जींद के लिए कुछ डिवैल्पमेंट का काम क्रिया ये जिस तरह भोले-भाले जमीदारों को गलतफहमी में डालते हैं, जिस तरीके से बरगलाते हैं, वह बड़ा ही खराब है । मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करता लेकिन इस सदन के अन्दर हरेक एम 0 एल 0 ए 0 के सामने लिखा हुआ है कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है इसलिए कुछ भाई जो यहां पर झूठ बोलते हैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए । हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं वे छिपाए नहीं जा सकते । आप 1968 से पहले के हरियाणा को ले लें और आज के हरियाणा को देखें । जमीन और आसमान का अन्तर है । इसकी जितनी तारीफ करें वह थोड़ी है । इस सरकार से पहले न सडके थीं, न नहरें थीं और न ही अस्पतालो का कोई इन्तजाम था और खास तौर से हमारा जिला जींद तो इतना पिछडा हुआ था कि जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जो जींद का महाराजा था उसके जमाने में कोई डिवैल्पमेंट का काम नहीं हुआ,

उसके बाद हम पैपसु में इग्नोर होते रहे और फिर ज्वायंट पंजाब में इग्नोर रहे और कुछ हमारी भी बदकिस्मती रही कि दल सिंह जैसे लीडर रहे जिन्होंने डिवैल्पमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब इस सरकार ने हमारे इलाके में कुछ काम किए हैं तब बहां के लोगों को महसूस हुआ है कि असली मायने में आजादी अब आई है । अब मैं चन्द तकलीफें जो हमारे इलाके के लोगों को है उनका जिक्र करूंगा लेकिन इससे पहले मैं यह जरूर कहूंगा कि इस सदन के अन्दर आदमी को थोड़ा बहुत झूठ बोलने से कतराना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब अनाज का संघर्ष चला उस वक्त चौधरी दल सिंह ने लोगों को बहुत वरगलाया, लोगों से नेम करवाया कि मंडी में कोई आदमी सरकार को अनाज देने के लिए न ले जाए, मगर जब अनाज मडियो में आने लगा तो इसके एजेंटों द्वारा प्रचार किया गया कि जो भी ले जाए वह दल सिंह की दुकान पर ले जाए । हमारे लोगों से 50-60 हजार रुपया इकट्ठा किया । इन्होंने अपना प्रोपैगन्डा करवाया कि दल सिंह ने जमींदारों के लिए यह किया वह किया । मैं कहता हूं कि इनके दिल में किसी की सेवा की भावना नहीं है ये तो भोले-भाले लोगों को गलत रास्ते पर डालते हैं । जब टीचरो की हड़ताल चल रही थी तो उस वक्त भी इन्होंने बच्चों के मां बाप से नेम करवाया कि वे अपने बच्चों को स्कूल में न भेजें —

Deputy Speaker ; Please do not be personal and speak on the Budget.

श्री फतेह सिंह : मैं तो यह बता रहा हूँ कि वे क्या करते चे हैं । टीचरों की जव हड़ताल चल रही थी तो भोले-भाले बच्चों के वालदेन से नेम ले लिया और अपनी घरवाली को जो टीचर है 18 तारीख को स्कूल भिजवा दिया और कह दिया कि हड़ताल पर न जाना ।

12.00 बजे

Chaudhri Partap Singh Daulta ; On a point of order, Madam. Can a .conduct of an opposition. M. L. A. be the subject matter of . discussion the way in which it is being done ?

Deputy Speaker ; It is not the subject matter for him. He is just mentioning something. But I have already checked hi that he should not be personal and that he should speak on Budget.

The hon. member may please continue his speech and speak on 'the Budget.

श्री फतेह सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबी, मैं यह बिल्कुल फ़ैक्ट्स बता रहा हूँ गलत बात नहीं कही जा रही है । भोलेभाले जमींदारों को बहका कर अपना उललू सीधा करते रहे । दूसरी तरफ़ अपनी औरत से यह लिखवा कर दे दिया कि हड़ताल न करो और दूसरे लोगो को अपना उल्लू सीधा करने के लिये बहकाते न्हे । डिपटी स्पीकर साहिबा, मे रा कहने का मतलब यह है कि ऐसी ऐसी गलत बातें तो ये लोग खु द करेसे रहे और सरकार का नाम

यू ही बदनाम करने को कोशिश कर रहे हैं -शोर- तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कुछ अपने हल्के के मुताल्लिक यहां पर जिक्र करना चाहता हूं कि जुलाना एरिया जो है वह बहुत ही ड्राई एरिया है वहां 80, 70 हाथ के करीब पीने का जो पानी है, वह खारी है, तो आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है जैसे कमाचखेडा, करेला, झमोला, किरसोला गढ़वाली तथा खेड़ा बख्ता वगैरह-वगैरह, इन गांवों की एक बैल्ट सी बनाकर पीने के लिये मीठा पानी मुहैया किया जाए । इसके साथ साथ जुलाना के लिये मैं कुछेक बातें और कहना चाहती हूं कि यह एक सब डिविजन बन गया है, एस ० डी ० ओ ' (सिवल), एस ० डी० ओ ० नहर तथा बिजली बी एण्ड आर, पी ० डब्ल्यू० डी ० वहां है लेकिन वहां पर न ही दफतर है, और न ही कर्मचारियों के रहने के लिये कोई क्वार्टर हैं, तो इस तरफ मैं चाहूंगा कि सरकार पूरा-पूरा ध्यान दे और जुलाना एक सैन्ट्रल ब्लेस है, ' वहां पर मन्डी भी है । इसके साथ यह होगा कि लोगों को हर तरह को सहूलियतें वहीं पर ही मिल जाएंगी । और वहां 'पर कुछ गांव ऐसे है जहां पर सैन्डी एरिया होने के कारण पानी नहीं पहुंचता है, वैसे यह कमाडिड एरिया है, वहां पर पक्के खाल बना दिये जाएं तो इससे जमींदारों को बहुत फायदा होगा । इसके लिये चाहे जमींदारों के ऊपर ही खर्चा क्यों न पड़े तब भी वे लोग इस के लिये तैयार हैं । तो सरकार से आपकी मार्फत अपील करूंगा कि इस तरह करने से लोगों को हालत भी सुधरेगी । यह गाव है गतोली, कमाच खेड़ा, दांरड, मालवी, देस खैडा, करेला,

झमोला, किरसोला व झमोला के लिये पक्के खात बना दिए जाएं जिस से 5/6 हजार एकड़ रकबा फालतू आबपाश होगा । इसके साथ साथ बुचाना, बरारखेडा, इगरा और बेबलपुर के बारे मे भी जिक्र करना चाहता हूं । वह बरारखेडा, आर ० डी ० नं ० 4 और 7 के दरमियान से एक सब माईनर निकाल दी जाएं और खालों को पक्का' किया जाए तो इससे काफी फायदा ही सकता है । इसके साथ साथ अगर चाबरी माइनर को एक्सटैन्ड कर दिया जाए तो उससे नुडाना नडानी और पडाना इन गांवों को बहुत फायदा होगा और यह आबपाशी के लिये बहुत मुफीद साबित हो सकता है चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बारे में एलाउस भी किया था । बराहे कलां और सुन्दर दूरी पर है गांवों में पक्की खालें बनाई जाएं तभी यहां पर रकबा आबपाशी हो सकेगा । इससे लोगो की पैदावार अधिक होगी । कई गाव ऐ से हैं जहां पर पीने का पानी नही है और दूरी पर है जैसे करेला झमोला, किरसौला व बुडा खेडा कई ऐसे गांव हैं, इन गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम होना चाहिये । इसलिये यहां पक्के खाल बनाए जाने चाहिये और यहां तक कि इन गांवों के लोग अपने पास से इन सभी का खर्चा देने के लिये तैयार हैं तो मैं आपकी मार्फत सरकार से अपील करूंगा कि शीघ्र ही इस तरफ ध्यान दिया जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक मालवी गांव है इसके साथ ही थोड़ी दूर से मालवी माइनर गुजरता है इस गांव का सारा रकबा वैस्ट साइड पर है । इस माइनर पर एक पुल बना दिया जाए, गाँव वालों को बहुत दूर से घूम कर करना पड़ता है तो इसलिये गांव के साथ इस माइनर

पर पुल जरूर बनाया जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके साथ-साथ कुछ मीर गाँव जैसे अकालगढ, दौरड व कमाच खेड़ा, फतेहगढ, बामन वास इनको सब माइनर से मिलाया जाए, या इनके पक्के खाल बनाकर इनको नहर सुन्दर ब्रीच से आबपाश किया जाये ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके । इसी तरह से इगरा और बैवल पुर वगैरह को भी पक्के खाली से आबपाश किया जाए ताकि आबपाश में बढ़ोतरी हो सके । इसके साथ -साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यहीं पर कुछ सड़कों के बारे में कहना चाहता हूँ जोकि बहुत छोटी छोटी सी हैं और अगर इन सड़कों के छोटे-छोटे टूकड़ो को पुरा कर दिया जाता है तो जुलाना जो है वह बड़ी रोड से चारों तरफ से मिल जाता है इससे लोगों को आने-जाने में बड़ी सहूलियात होंगी । ये चार सडरके हैं :-

1. जुलाना से भिवानी, को कुनैक्ट करने के लिये देवरड से फरवाना ।
2. जुलाना से गोहाना को कुनैक्ट करने के लिये लजवाना-कलां से रिढाणा यह तो सिर्फ डेढ मील का टुकड़ा है ।
3. जुलाना से सफीदों को कुनैक्ट करने के लिये नन्दगढ से भैरों खेड़ा या लुदाना ।
4. जुलाना से हांसी को कुनैक्ट करने के लिये मालवी से बडछप्पड़ या करेला से ।

तो अगर इन सड़कों को, जिनके छोटे-छोटे टुकड़े अभी बनने वाले हैं, बना देने से जुलाना मेन रोड से मिल जाता है इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार से यह पुरजोर अपील करुगा कि इन सड़कों को जल्द से जल बना दिया जाए । यह सारा टुकडा जो बनने वाला होगा वह करीबन ह मील का ही होगा तो इसके लिये सरकार को कोई भारी खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा । इससे जुलाना की जो मण्डी है उसको और स्टेट को भी फायदा होगा और साथ में लोगो के आने-जाने के लिये कोई दिक्कत नहीं होगी । (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बस मैं एक दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाकर अपना भाषणा खत्म करुंगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो जुलाना और जींद का एरिया है, यहां कमाद बहुत होता है, यह कमर्शियल पवांयट आफ व्यू से बहुत अच्छा है । सरकार को चाहिये की वहां की सर्वे करवाये और जींद और बुलाना के अन्दर गन्ने की एक एक मिल लगा दी जाए तो वहां लोगो की कुछ हालत सुधार सकती है और लोगों की भलाई के लिये यह एक अच्छा कदम होगा । इसके साथ साथ आगे मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जींद के साथ-साथ पडारा है, धार्मिक स्थान है टूरिजम विभाग की मारफत वहां पर ऐसी कोई न कोई धार्मिक चीजे बना दीं जाएं तो यह जुलाना और जींद की लोभा के लिये बहुत अच्छी बात होगी । इस से आगे मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हरिजनों की बहुत सी चौपाले रुकी हुई है

और फायनैन्स की वजह से रुकी पडी हैं तो मैं आपके द्वारा सरदार से यह प्रार्थना करता हूँ कि हरिजनों की निगम के द्वारा सहायता करवाएं जोकि उन गरीबों के लिये बड़ी लाभदायक बात होगी इसलिये अन्त में मैं फिर इन सारी बातों का तरफ सरकार की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मैंने यहां पर जो जो सुझाव अपने हल्के के मुताल्लिक रखे हैं, उन पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाए और दूसरे कामों से पैसे की बचत करके हमारे इस इलाके को प्रैफरैन्स दी जाए ताकि वहा के रहने वाले गरीब हरिजनों, गरीब किसानों को फायदा हो सके ।

कृषि मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन में तीन दिन से बजट पर बहस हो रही है । इसमें बहुत से सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये और दो-तीन माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें भी कहीं जोकि उनकी आदत के मुताबिक है हाउस में कभी घी ये वास को ठीक नहीं कहते । उनमें से चौधरी दल सिंह जी ने खास तौर से यह कहा कि अनाज की समगलिंग हुई और सीड में घपला हुआ है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा उनको यह बताना चाहता हूँ कि जहां तक सीड का ताल्लुक है भारत सरकार के आदेश के अनुसार कि सर्टीफाइड सीड के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है वह सारे देश के अन्दर जा सकता है, इसमें प्रान्तीय सरकारों का कोई दखल नहीं है, पता नही चौधरी दल सिंह ने कहां से ऐसी बात सुन ली? जहां तक महकमे का ताल्लुक है महकमे ने कोई सीड प्रचेज नहीं

किया । अलबत्ता एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी का सीड महकमे ने जरूर बेचा है रोकि 160 रुपये के भाव से बेचा गया । लेकिन बाद में सरकार ने महसूस किया कि यह भाव मंहगा है इसलिये हमने 160 से घटा कर उसे 125 रुपये के हिसाब से बेचा । लेकिन महकमे ने बाहर से सीड मंगवा कर कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे गड़बड़ हुई हो । इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि जिस आदमी का जेसा ध्यान होगा, जैसा ख्याल होगा और जैसी विचारधारा होगी वह हर आदमी को वैसा ही समझेगा । ये या तो किसी सबूत के साथ बात कहते लेकिन जिस बात का सिर-पांव ही न हो, वह हाउस में कह ही जाए तो किसी का मूंह तो पकड़ा नहीं जा सकता । लेकिन इन्होंने हाउस में गल्ल बात कही कि हमने सीड देने में घपला किया । हमने सीड उनको दिया है जिनको भारत सरकार ने रिकमेंड किया था या उनको दिया जहां की सरकार ने नौमीनी मुकर्रर करके यहां भेजे लेकिन किसी किस्म की हेराफेरी वाली बात नहीं हुई । भारत सरकार ने हमें यह भी कहा कि दूसरे प्रान्तों में अच्छा बीज नहीं बनता है, आप के प्रान्त में ही अच्छा बीज बनता है । इसलिये आप अच्छा बीज बना कर आसाम, बिहार, वैस्ट बंगाल और महाराष्ट्र आदि को दें । हम इस बिना परसीड कार्पोरेशन भी बनाने जा चे हैं ताकि दूसरे प्रान्तों को भी अच्छा बीज दे सके और अपने यहां भी किसनो को अच्छा बीज मुहैया कर सकें । अच्छा सीड पैदा करके हमने अच्छा काम किया है कोई बुरा काम नहीं किया है । दूसरी बात यह है कि इस बार चने के सीड की बहुत कमी रही क्योंकि पिछले साल घना कम पैदा हुआ

। चना कम पैदा होनेकी वजह से हमने राजस्थान से 12,000 क्विंटल चने का सीड मंगवा कर किसानों को 185 रुपये क्विंटल के भाव से दिया जबकि उसकी मार्केट प्राइस 225 रुपये क्विंटल थी । हमने किसानों को ठीक और मुनासिब कीमत पर बीज देने की कोशिश की बै । जहां तक इन्होंने कह पैदावार में क्या इजाफा हुआ है? मैं एक बात चौधरी दल सिंह जी को 67- 68 में भी 39.50 लाख टन अनाज हुआ था लेकिन इन्होंने यह नहीं सोचा कि कुदरत पर भी कुछ बातें डिपेंड करती हैं । 1967- 68 में 12.40 लाख टन चना हुआ था और 46.60 लाख टन बाजरा हुआ था । यह एक ऐसी क्राप है जो नेचर पर डिपेंड करती है । जिस समय अच्छी बरसात हो जाए या अच्छा सीजन लग जाए तो चना ते बहुतही अच्छा हो जाता है । मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि उस समय गेहूं कितना पैदा हुआ और बाजरा कितना पैदा हुआ? 1966- 67 में साढ़े दस लाख टन गेहु पैदा हुआ । लेकिन पिछले साल भाखड़ा में पली कम होने की वजह से बिजली को कमी रही और नहरों में भी पानी कम चला औत गर्म हवाएं चलीं उसके बावजूद भी हमने साढ़े इक्कीस लाख टन गेहूं पैदा किया और उससे पिछले साल 24 लाख टन गेहूं पैदा किया था और 1971- 72 में हमने साढ़े सैंतालीस लाख कम अनारु पैदा किया । इसी तरह से धान को लो, 1966- 67 में जहां 2, 23,000 टन चावल पैदा होता था आज इस साल तह 560000 टन पैदा हुआ है । ये तो सिर्फ एक बात कोही लेकर चल पड़े लेकिन इनको पता होना चाहिये कि नेचर पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है । इसके

साथ-साथ इन्होंने होल सेल ट्रेड में सरकार की बड़ी भारी आलोचना की कि सरकार की यह गलत पालिसी थी । तो क्या कोई बताने वाला है कि सरकार को क्या गलत पालिसी थीं? हमने ठीक भाव पर अनाज खरीदा और ठीक भाव पर बेचा । अगर यह सरकार होल सेल ट्रेड टेक ओवर न करती तो पता है गरीबों की क्या हालत होती? गरीबों को आज गेहूं 3- 4 सौ रुपये क्विंटल के भाव से मिलना था अगर ऐसा होता तो जिस गरीब आदमी ने अनाज मोल लेकर खाना है बताओ वह क्या करता ? चौधरी दत्त सिंह ले यह भी कहा कि अनाज का टारगेट इसलिये पूरा नहीं हुआ कि अनाज को समगलिंग हाँ गई । मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जब 24 लाख टन लाख पैदा हुआ तो उस साल भी हमने 8 लाख 18 हजार टन प्रक्योर किया और 15/16 लाख टन स्टेट में अपने खाने के लिये रहता है । इस बार साढ़े 21 लाख- टन पैदा हुआ जिसमें से 5. 90 लाख टन हमने सेंट्रल पूल में दिया और 15- 18 लाख टन अपने खाने के लिये वे स्टेट में रहा है पिछले सालों की तरह इस बात से भी इन्कार नहीं करता कि हो सकता है कहीं पर थोड़ा सा अनाज समगल हो गया हो क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ में राज-स्थान है और तीन- सौ मील लम्बा वार्डर इतने लम्बे वार्डर के ऊपर सभी जगह तो हमारे आदमी नहीं रह सकते इसलिये हो सकता है कि कोई ऊंट या सिर पर उठा थोड़ा बहुत अनाज ले गया हो, क्योंकि खेत के साथ खेत राजस्थान दिल्ली और हरियाणा का लगता है । 15 लाख रुपये के करीब हमने अनाज पकड़ा जो बाहर जा रहा था । हमारे

फूड डिपार्टमेंट और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने हर संभव कोशिश की कि अनाज समगल न होने पाए । इसलिये बड़े पैमाने पर कोई समगलिंग नहीं हुई, इनको तो गलत बात कहने की आदत है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : अगर दो चार सेर अनाज चला भी गयी तो कौनसा पाकिस्तान चला गया, हिन्दुस्तान में ही गया होगा ।

चौधरी भजन लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे कहने का मतलब है कि प्रक्योरमेंट भी हमने जो हमारी स्टेट में अनाज पैदा है उसके मुताबिक की । चाहे इस साल के आंकड़े भी मिला कर देख लो और पिछले साल के देख लो, हमने ठीक किया है । एक बात चौधरी चांद राम जी ने कही कि जो हवाई छिड़काव हुआ गन्ने पर, उसके नीचे यानी हवाई छिड़काव के नीचे फिरते आदमी नहीं मरे, मैं उनको क्या कहूं या उनको दवाई के बारे में ही नहीं पता और या फिर ये खेतों में नहीं गये जहां छिड़काव हो रहा था । इनकी तसल्ली तो तभी होती अगर दो-चार आदमी मर जाते । मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि दवाई छिड़कने से कीड़े मरे या नहीं मरे? अम्बार हम खेतों में दवाई न छिड़कते तो गन्धे की फसल को बीमारी से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता । डिप्टी स्पीकर साहिबा, दवाई— दो किस्म को होती है । एक दवाई इस किस्म की होती है जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता उसका नाम है यू. सी. वी0 और लो वोलियम की है और दूसरी का नाम है एच .

वी. एस . यह हाई वोलियम को होता है और इममें पानी का मिलान होता है । तीसरी दवाई जिससे आदमी मर जाते हैं उसका नाम मलोथियन इसकी बदबे भी काफी गन्दी होती है और इसकी अगर आदमी सूँघ भी ले तो भी उसके मरने के चांसिज होते हैं लेकिन इन दवाइयों से आदमी नहीं मरते इससे सिर्फ कीड़े ही मरते हैं । गले पर हमने जो स्परे किया उससे गले की बीमारी नहीं रही । किसी भी खेत में अगर स्परे न होती तो गन्ने के अलावा दूसरी फसलों पर भी इस बीमारी का प्रकोप पड़ता । लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे बात कह दी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस स्परे के काम पर भी 35 लाख के करीब खर्च किया गया है जिसमें से आधा खर्च हमने भारत सरकार से लिया है और आधा उस एरिया के मिलों से लिया है जहां छिड़काव किया गया था । किसानों के ऊपर हमने बहुत कम खर्च डाला है । अनाज के बारे में मैंने जैसे आपको बताया इन्होंने काफी गश्त बातें को हैं । रूई में भी हमने बड़ी भारी प्रगति की है । 1966-67 में 2,88 हजार गांठें रूई की बनी आज साढ़े चार लाख गांठें रूई की बनती हैं । इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक खाद का ताल्लुक है इस बात को मैं भी महसूस करता है कि खाद की सारे देशों में कमी है और उस का कारण यह है कि बहुत सी खाद हमारे मुलक में बाहर के देशों से आती है और वहां पर भी चुंकि खाद कम बनती है इस लिए सैट परसंट कमी पूरी नहीं हो सकती । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस वक्त हरियाणा बना था उस वक्त यहां पर 68 हजार टन खाद लगती थी और पिछले साल में खाद

की कभी होने के बावजूद भी व लाख 71 हजार टन खाद हम ने किसानों को दिया और इतना इस्तेमाल हुआ । इस साल हमने भारत सरकार से कहा था कि 9 लाख 80 हजार टन खाद हमें चाहिए हरियाणा के लिए लेकिन उन्होंने साढ़े सात लाख टन हमें अलाट किया है जिस में से 5 लाख टन हमें मिल भी गया है । भारत सरकार ने दूसरी ग्रांटों के सिलसिले में भी हमारा पूरा ध्यान रखा है और वह हमारी पूरी-पूरी सहायता भी करती है । इस के साथ-साथ हमने पैडी बोने के समव खरीफ कैम्पेन चलाई, उस के लिए हम ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 100 एक्सपर्ट्स बुलाए और उनकी टीम मुकर्रर को ताकि वे लोगों को जा जा कर समझाएँ कि पैडी को किस तरह से और कितना-कितना खाद देना है और उसमें किस तरह से बीमारियों बगैरा से बचाना है । यह उसी का ही नतीजे है कि आज हम सारे देश में चावल की पर एकड़ ईल्ड के हिसाब से सब से आगे हैं । इसी तरह से हम ने खूबी कैम्पेन के लिए भी तीन सी एक्सपर्ट्स एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी से मंगवाए और एक हजार गांवों में किसानों को डिमौन्स्ट्रेशन के जरिए सारी बातें बताई कि किस तरह से और कितनी कितनी मिकदार में बीज और खाद का इस्तेमाल करना है । इस के अलावा हम ने पानी और बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसे किया कि जिस एरिया में पहले फसल बोई जानी है वहां पर उसी एरिया की क्राप और सोइंग के लिए वैस्टर्न जमुना कैनल का पानी भाखड़ा कैनल में दिया और भाखड़ा कैनल का पानी वेस्टर्न जमुना कैनल में दे दिया, जिस एरिया के लिए पानी चाहिए था वहां जरूरत के

मुताबिक पुरा पानी दे दिया, जहां पैडी के लिए चाहिए वहां पहले पैडी को दे दिया और अगर काटन के लिए जरूरत पड़ी तो वहां का पानी वहां पर दे दिया और इसी तरह से हम ने बिजली भी दो ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सकें । इस के अलावा वर्ल्ड बैंक को मदद से हम ने पांच साल में 11 हजार ट्युबवैल लगाने थे लेकिन हम वह दो साल में लगा कर सारे देश में अक्वल चे । हम ए .आर .सी . स्कीम के तहत 30 हजार ट्यूबवैल और लगाने जा रहे हैं । हमारे प्रान्त में कुल 115 लाख एकड़ भूमि है जिस में से 9 लाख एकड़ भूमि कलर और शोर की है और वह खराब हो गई है । हम उसको रिक्लेम करने जा रहे हैं । हम ने उस के लिए भारत सरकार से सहायता ली है । हमे 19 करोड़ रुपया ए.आर.सी. ने उस जमीन को रिक्लेम करने के लिए दिया है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के इलावा 6 लाख एकड़ भूमि और ऐसी है अगर उस को हम ने कंट्रोल न किया तो उस में भी शोर कलर और हो जायेगा । तो उस के लिए हम ने पहले प्रोग्राम बनाया है । हम ने पहले करनाल में रिक्लेमेशन का काम शुरू किया है, अगर कोई भाई देखना चाहे तो वहां पर जा कर देख सकता है कि कितना अच्छा काम हो रहा है । हिसार जिला में 18 करोड़ रुपया हम ने काटन की पैदावार बढ़ाने के लिए रखा है । हम अढ़ाई लाख एकड़ में पहले से और ज्यादा 320 एफ काटन को काश्त करवाएंगे और इस के इलावा 320 एफ काटन का बढ़िया बीज लोगों को देंगे जिस से कि काटन की पैदावार हमारे प्रान्त में बहुत बढ़ जाएगी । इस के साथ साथ हमारी जो एग्रीकलचर

युनिवर्सिटी है यह केवल हिन्दोस्तान में ही नहीं बल्कि जापान को छोड़ कर अगर मैं कहूँ सारे एशिया में टोप पर है तो यह कोई गलत बात नहीं होगी । जहां तक मिल्क प्लांट का ताल्लुक है यह हम हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर मिल्क प्लांट लगाने जा रहे हैं और हमारी जो प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का गरीबी हटाओ प्रोग्राम है उस को पूरा करने में इस स्कीम से बहुत मदद मिलेगी । इस में हर गरीब कदमी और छोटा किसान, चाहे वह हरिजन है चाहे और जाति का है, हर गरीब आदमी चार पांच भैसे रख कर दूध बेच कर अपना गुजारा कर सकेगा । इस के साथ-साथ मफाल और एस.एफ.डी.ए. के तहत हमारी कुछ स्कीमें हैं । इस के तहत हम 25 परसेंट से लेकर 33 परसेंट तक हम गरीब आदमियों को सबसिडी दे रहे हैं । और इन स्कीमों के तहत हम ने 10 करोड़ रुपए केलोन दिए हैं और भारत सरकार न हमारे इस काम की बहुत प्रशंसा की है । इसी तरह छोटे किसानों को सुविधा के लिए जो लोग ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते उनकी मदद करने के लिए हम देहातो में एग्रो-ईंडस्ट्रीज सेंटर खोल रहे हैं । हम हर ब्लाक में यह सेंटर खोलने जा रहे हैं और उन सेंटरों में तीन तीन, चार-चार ट्रैक्टर रखे जाएंगे ताकि थोड़ी-थोड़ी जमीन वाले लोग ट्रैक्टर हायर करके खेती से पूरा फायदा उठा सकेंगे इस से भी लोगो को बहुत सुविधा मिलेगी । तकावी का जहां तक ताल्लुक है जिस वक्त डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा बना उस वक्त किसानों को एक करोड़ 59 लाख रुपया. कर्जा मिलता था लेकिन आज 1972-73 मे हम ने 39 करोड़ रुपया किसानों को कर्जे के रूप में

दिया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि टाईम थोड़ा है और मित्तल साहब ने बोलना है इस लिए मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता और आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन मੈंबरों ने बेबुनियाद बातें कहीं एं उनको ऐसी बातें नही करनी चाहिए थी, वाकी चिन मँबर साहिबान ने ठीक सुझाव दिए हैं उन के ऊपर सरकार विचार करेगी और जहां तक हो सकेगा उनके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करेगी। इतना कह कर मैं अपना स्थान लेता हूँ।

वित्त मंत्री (श्री रामसरन चन्द मित्तल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इस बजट पर बोलते हुए ज्यादा तर माननीय सदस्यों ने इस का स्वागत किया है जिस के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। विरोधी दल के और इन्डीपेंडेंट मँबरो ने भी ज्यादातर इस का स्वागत किया है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मित्तल साहब, मैं ने भी इस का स्वागत करना था इस लिए उस लिस्ट में मेरा भी नाम दर्ज कर लीजिए।

श्री रामसरन चन्द मित्तल : आप का नाम भी दर्ज कर लिया है मैं ने अपनी लिस्ट में और मैं आप का भी धन्यवादी हूँ जो आप दे इस को सराहना की है। डिप्टी सीकर साहिबा दो चार मँबरो ने इस का काफी नुक्ताचीनी की है, नुक्ताचीनी करना तो वैसे उनका हक भी है और सरकार को भी उनकी नुक्ताचीनी पर

पूरा ध्यान देना चाहिए । लेकिन नुकताचीनी कई प्रकार की होती है, एक तो महज नुक्ताचीनी के लिहाज से ही की जाती है और दूसरी होती है अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कभी रह गई हो तो उस को दुरुस्त करवाने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया जाता है ताकि वह गलती ठीक कर दी जाए । लेकिन जो महज नुक्ताचीनी के लिए यहां बातें करते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता मगर जो कंस्ट्रिक्टिव नुक्ताचीनी हो उस पर सरकार विचार करती वै । मैं मैनबर साहिबान को यह बताना चाहूंगा कि हमारी हरियाणा को जो इकानोमी है वह बहुत साऊंड है बावजूद इस बात के कि. इस को कई प्रकार के धक्के लगे । आप जानते है कि जब जब देश के अन्दर जंग हुआ, जिस किसी ने वह जमाना देखा हो, 1914, 1918 की लड़ाई ओर उस के बाद फिर दूसरी जंगे स्कीम हुई और उस के बाद इन्डो-पाकिस्तान वार हुई, तो जब जब लड़ाईया हुई तो उस से चीजों को कीमते बडी और मंहगाई हुई । तो हमारा देश भी इन बातों से खाली नहीं है । वार के बाद जब प्राइसिज बढ जाती है तो हर एक बजट पर उनका असर पड़ता है । इसके अलावा दो तीन फैक्टर्ज हैं जिनका हमारी इकानोमी पर असर पड़ा जैसे कि आबादी का बढ जाना और फिर इन्द्र भगवान का समय पर बारिश न करना और अगर करनातो कम करना । इन बातों का इकानोमी पर बहुत असर पड़ता है । हमारी इकानोमी पर इन तमाम बातों का असर पड़ा, पावर शार्टेज हुई और फूड ग्रैन्ज की प्रोडक्शन पर भी बुरा असर पड़ा लेकिन इन बातों के बावजूद हमारी हालत अच्छी रही क्योंकि हमने शुरू-शुरू

में जो इलैक्ट्रिकेशन हरियाणा में की और एग्रीकलचर को तरक्की देने के बारे में जो बातें की वजह से हमारी अर्थ व्यवस्था बुरे हालत के बावजूद भी बहुत अच्छी रही । आईसिज का बढ़ना न सिर्फ इस प्रदेश और देग का मसला है बल्कि यह आल वर्ल्ड फिनामेनन है हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी इस बारे में कई जगह कहा है कि ऐसी चीजे जो हुई है इनका हमारे देश पर ही नहीं सारे संसार पर इनका असर पड़ा है । तोइस में घबराने की कोई नहीं है हमारी इकानोमी बहुत अच्छी है, साऊंड है, अच्छी रहेगी और ईश्वर ने चाहा तो ज्यादा भी अच्छी रहेगी क्योंकि हमारा वेस बहुत मजबूत हैं । बजट के बारे में यहां विरोधी दल के कुछ भाईयों ने कहा कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है और करोड़ों रुपए हमें सूद के देने पड़ते है । ठीक है जब कर्जा लिया है तो करोड़ों रुपए हिसाब से ब्याज के भी देने पडते हैं । लेकिन हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम अपने प्रांत की तरक्की करना चाहते हैं और उम्रके लिये हमारे पास अगर साधन नहीं हैं पैसा नहीं हैं (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) तो हमें कर्जा लेना पड़ेगा और अगर नहीं लेगे तो तरक्की के काम नहीं कर सकेंगे. जब कोई आदमी नया नया अपना विजनैस सैट अप करता है तो जो उसके पास पैसा होता है वह अपने पास से भी लगाता है और फिर भी अगर काम न चले खो कर्ज भी लेता हैं । इसी तरह से सरकार भी करती है और तरक्की के कामों के लिये कर्ज लेकर काम चलाती है, उस रकम पर सूद भी देते हैं और फिर असल भी अदा कर देते हैं । हम भी प्राईवेट बिजनैसमैन की

तरह से काम करते हैं कि काम चलाने के लिये कर्ज लेते हैं । जब हरियाणा बना था तो हमारे पास रिसोर्सिज नहीं थे और उस वक्त लोग तो यह कहते थे कि हरियाणा तो बन रहा है लेकिन शायद यह अपने मुलाजिमों को तनखाह भी न दे सके । आज आप देखें हमारी इकानोमी कितनी अच्छी है और यही लोग जो ऐसी बातें करते थे हरियाणा के बारे में आज तारीफ कर रहे हैं और साथ में हैरान हो रहे हैं कि इतनी भारी तरक्की कर ली इस थोड़े से अर्स में अभी फायनैस कमिशन ने कर्जा के बारे में कुछ हिसाब लगाया है कि हर स्टेट को कर्ब पर कितना व्याज देना पड़ता है और अगले पांच साला प्लान में कितना कर्जा हो जायेगा और कितना व्याज देना पड़ेगा । उन्होंने पांच साल के लिये हिसाब लगाया है कि 64 करोड़ रुपये हम को देने पड़ेंगे लेकिन दूसरे प्रांतों पर यह रकम कितनी पड़ेगी वह मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि उनके मुकाबले में हमारी पोजीशन क्या है । तो राजस्थान के जिम्मे यह 375 करोड़ रुपये आयेगा, आंध्र प्रदेश के 201 करोड़, महाराष्ट्र के 246 करोड़, उत्तर प्रदेश के 270 करोड़ और वैस्ट बंगाल के जिम्मे यह रकम होगी 207 करोड़ रुपये होगी इसी तरह और प्रदेशों के फिगरज भी मेरे पास हैं लेकिन मैं उन सब में नहीं जाना चाहता । मेरे कहने का मतलब यह है कि कर्जा लेना और सूद उस पर देना कोई डैमेजिंग बात नहीं है यह तो तरक्की की निशानी है कि हम रिसोर्सिज जो हमारे अपने हैं उनको तो लगाते ही हैं लेकिन तरक्की के लिये कर्जा भी लेते ताकि बहबूदी के काम ज्यादा से ज्यादा हो । कर्ज अगर लेते हैं

तो कोई बुरी बात नहीं है । लेकिन इस में देखने वाली बात जो है वह यह है कि जो कर्ज लिया जाता है वह खर्च कहां किया जाता है । अगर एक प्राइवेट आदमी कर्ज लेकर शादी विवाह पर खर्च कर देता है तो यह नुकसान वाली बात है लेकिन अगर उस पैसे को बिजनैस पर लगायेगा तो फायदा होगा । इसी तरह मैं अर्ज करता हूँ कि हमने जो पैसा कर्ज लेकर इम्बैस्ट किया है वह प्रोडक्टिव कामों पर किया है जिससे प्रांत को फायदा पहुंचे प्रांत की पैदावार बढ़े और आमदनी बढ़े और हमें इससे जो फायदा पहुंचा है वह कहने की बात नहीं सब जानते हैं हर जगह तारीफें हो रही है प्रांतीय लेवल पर भी और नैशनल लेवल पर भी । चौधरी राम लाल जी ने ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरैंडम के पेज 18 को पढ़ कर उस पर यह एतराज किया कि उस में जो 8.06 करोड़ फिगर उसमें दस लाख कर डिस्क्रेपेंसी है । अगर वह उसकी डिटेल्ज में जाकर देखे तो उनको पता लग जायेगा कि ये फिगर्ज ठीक है और उसमें कोई डिस्क्रेपैसी नहीं है उसके । डिटेल्ज यह है, स्टैम्पस और रजिस्ट्रेशन + 2 लाख प्रापर्टी टैक्स + 5 लाख इलैस्ट्रिसिटी ड्यूटी 3 लाख इस तरह सारी रकम हिसाब में आ जाती है । यह कोई डिस्क्रेपैसी ऐसी नहीं है जिससे यह ख्याल किया जाये कि बजट में कुछ कमी रह गई है जैसेकि चौधरी राम लाल जी ने कहा । अब मैं प्वांयट बाई प्वांयट अर्ज करता हूँ । बिजली के बारे में यहां पर कई कुछ कहा गया । मैं समझता हूँ कि शायद इस बारे में मेरे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बिजली के मिनिस्टर साहब गुप्ता जी ने इस बारे में बड़ी

तफसील केसाथ बता दिया है लेकिन फिर भी है दो तीन बाते इस बारे में बताना चाहता हूं । जब ज्वायट पंजाब होता था और जब हरियाणा बना उस वक्त भी और जब तक यह बंसी लाल सरकार नहीं वनी थी उस वक्त तक भी यही होता था कि जब कोई किसान कुनैक्शन के लिये एप्लाई करता था तो हिसाब लगाया जाता था कि बिजली का खम्बा कहा पर है, और फिर उस किसान का घर कितनी दूरी पर वहां से है, कुनैक्शन देने पर खम्बों तारों ट्रांसफार्मर बगैरा पर किताना खर्च आयेगा और सारा हिसाब लगा का देखा जाता था कि क्या वह कुनैक्शन देना पेइंग प्रोपोजीशन है अगर है तो कुनैक्शन दिया जाता था वरना नहीं दिया जाता था । लेकिन जब यह सरकार आई इस ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया और यह कर दिया कि टयुबवैल के लिये जब कोई कुनैक्शन' मांगे तो चाहे उसका गांव दस मील पर हो बगैर घाटा मुनाफा देखे उसे कुनैक्शन दिया जाये । मैं अर्ज करता हूं कि लगभग तीन चार साल हुये सारे भारत के बिजली के मिनिस्टर्ज की एक मीटिंग हुई थी और उस में यह फैसला हुआ था कि 1 980 तक सारे भारत में आधे गांव को बिजली जरूर दे दी जाये लेकिन वह 1980 आने में तो अभी बहुत देर लगेगी । हरियाण सरकार ने 1970. के आस पास ही हरियाणा के सौ फीसदी गांव को बिजली दे दी । इसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा जो पहले अनाज के बारे में डैफिसिट था सरप्लस हो गया । इस बारे मे से एक ही जिला की मिसाल देता हूं । गेहूं का मामला में महेन्द्रगढ जिला हमेशा ही डैफिस्टि रहा है लेकिन 1972 में वही इतना अनाज हुआ

कि वह सरप्लस हो गया और अकेली नारनौल तहसील ने पचास हजार क्विंटल गेहूं बाहर भेजा । अगर इस में महेन्द्रगढ और दादरी के फिगर्ज भी शामिल कर दूं तो यह फिगर्ज और ज्यादा हो जाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली देने का नजरिया जो पहले उसे हम ने बदल दिया । हम ने कह दिया कि एग्रीकल्चरल प्रोडकशन के लिये जितनी बिजली किसान मांगे मांगे जहां चाहे दे दी जाये । यह ठीक है कि बिजली की कमी है लेकिन आप देखें बिजली की डिमांड एग्रीकल्चरल, इन्डस्ट्रीयल, ड्युमैस्टिक परपजिज और दूसरे कामों के लिये कितनी बढ़ गई है । इस लिये शार्टेज तो है, नी ही थी जिसे मीट करने के इन्तजाम भी सोचे और किये जा रहे हैं । कुछ शार्टेज इस लिये भी आई कि पानी कम बरसा इसलिये बिजली पं दा भी कम होने लग गई और यह सारी दिस्वरुत आई । लेकिन हम ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिये प्रायर्टी दी जाये और इस के लिये जितनी बिजली की जरूरत है वह पहले पूरी की जाये सब से पहले किसान को बिजली दी जाये उसके बाद इन्डस्ट्री- यल और फिर दूसरे परपजिज के लिये दी जाये । मैं समझता हूं बिजली पर एतराज करना तो हरियाणा के साथ अन्याय करना है । आज कितनी बिजली पैदा होती है और कितनी हमें मिलती है उसकी डिटेल्ज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । मैं आपको डि टेल्ज देना चाहता हूं कि कहां-कहां से कितनी-कितनी बिजली मिलती है । भाखड़ा नंगल प्रौजैक्त से 28 लाख यूनिट प्रतिदिन, इन्दपरस्थ स्टेशन से 12 लाख यूनिट प्रति दिन-, बदरपुर थर्मल प्लांट से 4

लाख यूनिट प्रतिदिन, राणा प्रताप सागर अटोमिक प्लांट से 5 लाख यूनिट प्रतिदिन और फरीदाबाद थर्मल प्लांट और सूरजपुर प्लांट से 3 लाख यूनिट प्रतिदिन मिलती है । इस तरह से हमें 52 लाख यूनिट प्रतिदिन इलैक्ट्रिसिटी मिल रही है । इसके अलावा, जैसा आपने गुप्ता जी के भाषण में सुना होगा, हम फरीदाबाद और पानीपत में थर्मल प्लांट लगा रहे हैं और कोशिश यह की जा ची है कि आयदा के लिए बिजली की कमी न व्हे । लेकिन एक रोज में ये सब काम नहीं होते, हर एक चीज के लिए रुपये की जरूरत होती है, प्लांट लगाने में टाईम लगता है लेकिन यह बात जरूर है कि बिजली की कमी को पूरा करमे की कोशिश को जा रही हूं इसके अलावा जैसा कि मैंने अपने भाषण में शुरू में कहा था कि हम ने 50 लाख टन अनाज पैदा करने का टारगैट इस साल रखा हुआ है और इसको पूरा करने की जरूर कोशिश की जाएगी । फर्टिलाईजर की कमी भी मिलती है, इस कमी को पूरा करने के लिए भी कोशिश की जा रही है जैसा कि आपको कल बताया गया था ।

स्पीकर साहब, हमारे खर्च के बारे में कुछ इतराज किए गए हैं । यह कहा कि साहब, एयर क्राफ्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है । दरअसल एयर क्राफ्ट को गलत तरीके से देखा गया है । यह 8 लाख रुपया महज एक ही हवाई जहाज के लिए नहीं है । इसकी डिटेल्ज आप देख लीजिए । 2 लाख 64 हजार रुपया सैलरी का है, इसी तरह से मशीनरी का है, एक्विपमेंट

का है, आफिसिज एक्सफैंसिज का है और इसी तरह की कई और चीजें हैं जिन का खर्च इसमें शामिल है । जैसे फ्यू ल आयल, रेडियो-एक्विपमेंट, इस्ट्रमेंट्स, मेन्टेनैस चार्जिज, टेलिफोन, पोस्टेज वगैरा वगैरा सब बातें इसमें शामिल हैं । जब तक आदमी एयर-माईडिंड न बने तब तक काम नहीं चलता आप देखें, दूसरे देशों में एरोप्लेन से बहुत ज्यादा काम लेते हैं । अगर वह यह कहे कि एरोप्लेन तब ले सकते हैं जब हमारे दूसरे काम पूरे हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा । इससे हमारे यहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है । स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं ताकि एयर सर्विसिज में जा सकें वरना हमारे लड़के दूसरी सट्टी के मुकाबले में पीछे रह जाएंगे । तो यह कहना कि एयर क्राफ्ट पर खर्चा ठीक नहीं तो यह गलत बात है. यह जरूरी चीज है, इसके अलावा जिसको एयर क्राफ्ट इस्तेमाल करने कि जरूरत पड़ती है । वह इस्तेमाल भी करता है । तो जो खर्चा इस पर हुआ है इस पर एतराज करने वाली कोई बात नहीं है ।

स्पीकर साहब, कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने इलाके की मांगे सदन में रखीं मैं उन मांगों पर इस वक्त जाना नहीं चाहता क्योंकि वे बहुत डिटेल में हैं, आफ हैंड कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन जो मांगे उचित हैं, रुपये पैसे के हिसाब से अगर वे मांगे ठीक होंगी तो पूरी की जाएंगी लेकिन इसको अश्योरेस के तौर पर न लिया जाए कि सब बातें जो कह दी हैं, जरूर हो जाएंगी । मैं ज्यादा न कह कर समाप्त करता हूँ ।

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2-00 P.M today,

(The Sabha then adjourned till 2-00 P.M. on Wednesday, the 16th January, 1974)

12.47 बजे